वर्ष 12 • अंक 284 • 18 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 16 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 2

जेट एयरवेज को मिले दो और प्रस्ताव

सुनील भारती मित्तल ▶▶ पृष्ठ 3

भारती एयरटेल का क्यूआईपी हुआ पूरा

डॉलर रु. 70.80 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 79.00 ▲ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39654 ▲ 179 रुपये | सेंसेक्स 41872.70 ▼ 79.90 | निफ्टी 12343.30 ▼ 19.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12378.00 ▲ 34.80 | ब्रेंट क्रूड 64.90 डॉलर (अपरिवर्तित)

एक नज़र

निर्यात में लगातार पांचवें महीने गिरावट

देश का निर्यात दिसंबर में 1.8 फीसदी घटकर 27.36 अरब डॉलर पर आ गया। यह लगातार पांचवां महीना है जब निर्यात में गिरावट आई है। वाणिज्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में भारत का आयात भी 8.83 फीसदी गिरकर 38.61 अरब डॉलर रहा। इससे व्यापार घाटा कम होकर 11.25 अरब डॉलर पर आ गया। दिसंबर 2018 में व्यापार घाटा 14.49 अरब डॉलर था। पेट्रोलियम आयात 0.83 फीसदी घटकर 10.69 अरब डॉलर जबकि सोने का आयात करीब 4 प्रतिशत गिरकर 2.46 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-दिसंबर 2019-20 के दौरान, निर्यात 1.96 प्रतिशत कम होकर 239.29 अरब डॉलर जबकि आयात 8.9 प्रतिशत घटकर 357.39 अरब डॉलर पर रहा।

65 टोल नाकों पर फास्टैग नियमों में 30 दिन की ढील

सरकार ने 65 चुनिंदा टोल पर फास्टैग के नियमों में कुछ समय की ढील दी है क्योंकि अभी वहां पथ-कर का ज्यादातर भुगतान नकद होता है। इन नाकों पर 25 फीसदी फास्टैग फीस वाले रास्तों को 30 दिन के लिए मिले-जुले भुगतान वाली लाइन में बदलने की छूट दी गई है। हाइब्रिड या मिली-जुली लेन में फास्टैग भुगतान और नकद भुगतान करने वाले, दोनों प्रकार के वाहन जा सकते हैं। ये टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था 30 दिन के लिए है।

2 ग्राम से कम वजनी गहनों पर हॉलमार्किंग जरूरी नहीं

सरकार ने दो ग्राम से कम वजन के सोने के आभूषणों और कलाकृतियों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की बुधवार को जारी अधिसूचना में पूरे देश में 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना दिया गया है। फिलहाल चांदी के गहनों और कलाकृतियों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से बाहर रखा गया है। वे सभी सराफ जो सोने के आभूषण बेचना चाहते हैं, उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के पास पंजीकरण कराना होगा। अब तक 28,849 से कम सराफों ने बीआईएस के पास पंजीकरण कराया है। पृष्ठ 18

जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगा मंत्रियों का दल

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के सकारात्मक प्रभावों और क्षेत्र के लिए सरकार के विकास कदमों के बारे में लोगों को अवगत कराने के वास्ते केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह इस महीने के अंत में जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगा। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रियों की जम्मू कश्मीर की यात्रा के कार्यक्रम को 17 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार यह यात्रा गृह मंत्री अमित शाह की पहल है और मंत्रालय इसमें समन्वय कर रहा है। पृष्ठ 18

कार्वी मामले में ऐक्सिस बैंक की अपील खारिज

सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग (केएसबीएल) के मामले में ऐक्सिस बैंक की अपील खारिज कर दी है। ऐक्सिस बैंक ने ब्रोकिंग कंपनी द्वारा उसके पास गिरवी रखे शेयरों को भुनाने की अनुमति मांगी थी। प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने 20 दिसंबर को सेबी से कहा था कि वह इस मामले में 15 जनवरी, 2020 तक आदेश पारित करे। पृष्ठ 3

त्यापार गोष्ठी

सरकारी अस्पतालों की बदहाली कैसे हो दूर?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या चीनी के लिए दोहरी मूल्य नीति होगी कारगर

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या आरकॉम के खरीदारों से बैंकों को बकाया वसूलने में मिलेगी मदद? हां **60.00%** नहीं **40.00%**

1 अरब डॉलर लगाएगी एमेजॉन

भारत में एमएसएमई के डिजिटलीकरण पर जोर देगी एमेजॉन

नेहा अलावधी और शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 15 जनवरी

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एमेजॉन के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी जेफ बेजोस ने आज कहा कि उनकी कंपनी भारत में सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए 1 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि एमेजॉन 2025 तक भारत में निर्मित 10 अरब डॉलर के साजोसामान के निर्यात के लिए अपने पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करेगी।

भारत में एमएसएमई पर आधारित अपनी कंपनी के पहले कार्यक्रम 'एमेजॉन संभव' में हिस्सा लेने आए बेजोस भारत की संभावनाओं के बारे में बोल रहे थे। अमेरिकी कंपनी की इस निवेश से भारत में एक करोड़ सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों को डिजिटल बनाने की योजना है। साथ ही भारतीय कारोबारियों को एमेजॉन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनियाभर में अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने में मदद की जाएगी।

एमेजॉन इन उपक्रमों को प्रशिक्षण देने और अपने कार्यक्रमों से जुड़ने की सुविधा देने के अलावा एमेजॉन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के जरिये क्लाउड प्रौद्योगिकी में भी मदद करेगी। इसके लिए इन उपक्रमों को कम लागत पर विशेषज्ञ सेवाओं की पेशकश की जाएगी।

फोटो: दलीप कुमार

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 'संभव' कार्यक्रम के दौरान एमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस और एमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल।

भारत में एमेजॉन

550,000
भारत में एमेजॉन पर विक्रेताओं की संख्या

18 लाख
एमेजॉन पे की मर्चेंट संख्या

100
डिजिटल हाट स्थापित करने की योजना, पड़ोस की और किराने की दुकान कार्यक्रम को फैलाने की भी योजना

800,000
कारीगरों व बुनकरों को एमेजॉन कारीगर प्रोग्राम के जरिये सक्षम बनाया गया

इस निवेश के हिस्से के रूप में एमेजॉन पूरे देश में विभिन्न शहरों और गांवों में 100 डिजिटल हाट स्थापित करेगी। बेजोस ने कहा, 'हम अब इस योजना की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि यह काम कर रही है। जब कोई योजना काम करती है तो आपको इस पर काम दोगुना कर देना चाहिए। मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मेरा अनुमान है कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। मैं भारत में जहां भी गया, वहां मैंने जबरदस्त ऊर्जा देखी।' (शेष पृष्ठ 18 पर)

विक्रेताओं पर चला बेजोस का जादू

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और एमेजॉन के मुख्य कार्याधिकारी जेफ बेजोस को सुनने के लिए बड़ी संख्या में विक्रेता जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे। बेजोस ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उनकी बातों ने वहां मौजूद दर्शकों पर जैसे जादू कर दिया। अमेरिकी उद्यमी ने कहा, 'हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की समृद्धि में हिस्सेदार बनें।' हालांकि कार्यक्रम के देर से शुरू होने पर इन्फोसिस के सह-संस्थापक और प्रमुख वक्ता एनआर नारायणमूर्ति नाराज दिखे। उन्होंने कहा, 'हमें डेढ़ घंटे की देरी हो गई है। मुझे 20 मिनट बोलना था लेकिन मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे देरी की आदत नहीं है।' व्यापारियों की संस्था कैट के विरोध के बावजूद एमेजॉन के कार्यक्रम में गजब का उत्साह दिखा। पृष्ठ 18

निर्यातकों को पूंजी उत्पाद पर रिफंड!

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 15 जनवरी

आर्थिक सुस्ती के बीच निर्यातकों की चिंताएं दूर करने के लिए सरकार आने वाले बजट में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नीति में बदलाव कर निर्यातकों को पूंजीगत उत्पादों पर चुकाए गए कर पर रिफंड की सुविधा दे सकती है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड को प्राप्त जानकारी के मुताबिक निर्यातकों को कर रिफंड सुविधा देने की घोषणा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में की जा सकती है। यह अलग बात है कि पूंजीगत उत्पादों की खरीद पर चुकाया कर लौटाने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद की मंजूरी मिलने के बाद ही लागू हो सकेगा।

...मिलेगी राहत

- पूंजी उत्पादों की खरीद पर चुकाए कर का मिल सकता है रिफंड
- बजट में निर्यातकों के लिए इस योजना का हो सकता है ऐलान
- जीएसटी परिषद की मंजूरी मिलने पर ही लागू हो पाएगी योजना

इस कदम से उन कारोबारियों को फायदा होगा जो उत्पाद या सेवाओं के निर्यात के लिए वचन-पत्र (एलयूटी) का मार्ग अपनाते हैं। अभी एलयूटी मार्ग से उन्हें अपने निर्यात बिल पर कर देने की जरूरत नहीं होती है लेकिन पूंजीगत उत्पादों पर चुकाए गए कर का उन्हें रिफंड नहीं मिलता है। बाकी सभी इनपुट टैक्स पर निर्यातकों को रिफंड सुविधा मिलती है।

नए नियम से निर्यातकों को पूंजीगत उत्पादों पर चुकाए गए कर के बराबर राशि की बचत होगी और अपने पास रकम आने पर वे उसका इस्तेमाल निर्यात बढ़ाने में कर सकेंगे। यह सुस्ती पर कुछ हद तक काबू पाने के लिए मददगार हो सकता है।

इसके लागू होने का सर्वाधिक लाभ उन कारोबारों को होगा जो उलटे शुल्क ढांचे का हिस्सा हैं यानी उनके उत्पादन एवं बिक्री पर लगने वाला कर पूंजी उत्पाद जैसे इनपुट पर लागू कर दर से कम है। मसलन, तैयार उत्पाद पर पांच फीसदी कर देने वाले कपड़ा विनिर्माता को कच्चे माल पर 18 फीसदी कर देना पड़ता है। इससे वह निर्यातक उपलब्ध क्रेडिट सुविधा का लाभ नहीं ले पाता है। हालांकि आईजीएसटी के अग्रिम भुगतान का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है लेकिन उलटे शुल्क ढांचे में शामिल कारोबारों के लिए यह मुफीद नहीं है। इसी वजह से निर्यातक एलयूटी मार्ग अपनाना ही पसंद करते हैं। उद्योग जगत का मानना है कि नई नीति आने से पूंजी-आधिक्य वाले क्षेत्रों से जुड़े निर्यातकों को विशेष लाभ होगा। टेक्सप्रोसिल के कार्यकारी निदेशक सिद्धार्थ राजगोपाल कहते हैं, 'अधिकतर निर्यातकों ने रिफंड प्रक्रिया मानवीय होने से एलयूटी मार्ग अपनाया था लेकिन पूंजी उत्पादों पर देय कर के एवज में उन्हें नहीं मिलने वाले रिफंड का आकार अब खासा बड़ा हो चुका है।'

जानकारों का कहना है कि नए प्रावधान में एलयूटी मार्ग और आईजीएसटी मार्ग अपनाने वाले दोनों तरह के निर्यातकों के साथ समरूपता बरती जानी चाहिए। पीडब्ल्यूसी इंडिया में अप्रत्यक्ष कर प्रमुख प्रतीक जैन कहते हैं, 'नीतिगत लिहाज से पूंजीगत उत्पादों पर चुकाए गए जीएसटी को बाकी इनपुट के समान माना जाना चाहिए और इस आधार पर निर्यातकों को रिफंड की अनुमति भी मिलनी चाहिए।' कंपनी जगत की यह मांग भी रही है कि श्रम-प्रधानता वाले क्षेत्रों की तुलना में पूंजी-आधिक्य क्षेत्रों को हतोत्साहित न किया जाए। पूंजी उत्पाद आयात करने वाले अधिकतर प्राथमिक निर्यातक निर्यात संवर्द्धन पूंजी उत्पाद (ईपीसीजी) को तरजीह देते रहे हैं। भारतीय निर्यात संगठन फियो के महानिदेशक अजय सहाय कहते हैं, 'पूंजी उत्पादों पर चुकाए कर का रिफंड शुरू होने के साथ ही ईपीसीजी योजना के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा।'

आम्रपाली मामले में बढ़ी जेपी मॉर्गन की मुश्किल

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 15 जनवरी

जेपी मॉर्गन इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आम्रपाली समूह के मकान खरीदारों के पैसों के 'वास्तविक लाभार्थी' की जांच कर रहा है। आम्रपाली समूह पर आरोप है कि उसने निवेश बैंकिंग फर्म के साथ मिलकर अपनी मुखौटा फर्मों के जरिये मकान खरीदारों के पैसों को कथित तौर पर विदेश भेजा है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत ईडी जेपी मॉर्गन इंडिया की भारत में संपत्तियों का मूल्यांकन कर रहा है ताकि अंतरिम तौर पर उसे जब्त किया जा सके। अदालत ने इसे धनशोधन-रोधी कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला बताया था। इसके बाद जेपी मॉर्गन द्वारा आम्रपाली समूह की फर्मों (आम्रपाली जोडिएक और आम्रपाली सिलिकन सिटी) में 85 करोड़ रुपये और 140 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े मामलों में विनिमय नियमों की जांच हो रही है। यह निवेश 2010 और 2012 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर किया गया था। फेमा मामले की सुनवाई के दौरान 19 लोगों/इकाइयों से पूछताछ की गई थी। इन कंपनियों के बीच कुल 1,100 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय से जुड़े लेनदेन शामिल हैं।

ईडी रिपोर्ट से पता चला है कि आम्रपाली समूह और उसके निदेशकों ने विदेशी निवेशक (जेपी मॉर्गन) के साथ मिलकर मुखौटा फर्मों और छद्म निदेशकों का जाल बुना और मकान खरीदारों के 140 करोड़ रुपये की हेरफेर की। इस लेनदेन के बारे में ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम्रपाली जोडिएक डेवलपर्स के शेयरों को कंपनी के प्रवर्तकों को सितंबर 2010 में 180 रुपये के प्रीमियम पर आवंटित किए गए थे और जेपी मॉर्गन इंडिया प्रॉपर्टी मॉरीशस कंपनी को 10 दिन के अंतराल पर ही 1,070 रुपये के प्रीमियम पर आवंटित किए गए। कारोबारी मॉडल में किसी तरह के बदलाव के बिना यह लेनदेन हुआ। बाद में कंपनी के प्रवर्तकों ने जेपी मॉर्गन से शेयर 2,280 रुपये, 2,560 रुपये और 3,000 रुपये की ऊंची कीमत में वापस खरीद लिए।

दिलचस्प है कि जब 2009 में आम्रपाली जोडिएक की शुरुआत हुई थी तो इसके 10 हजार अधिकृत शेयरों की पूंजी एक लाख रुपये थी और शेयर की कीमत 10 रुपये थी। कंपनी के प्रवर्तक अल्ट्रा होम्स को 7,500 और आम्रपाली होम्स को 2,500 शेयर आवंटित किए गए थे। एक साल से भी कम समय में अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई और इन्हें प्रवर्तकों को 180 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर आवंटित किया गया। (शेष पृष्ठ 2 पर)

धन की हेराफेरी

- वास्तविक लाभार्थी की जांच कर रहा ईडी
- विदेशी फर्म पर धनशोधन-रोधी कानून के उल्लंघन का है आरोप
- विदेशी फर्म से शेयरों को अत्यधिक ऊंचे दाम पर वापस खरीदे गए

दिल्ली : चुनाव के दौरान शराब की अवैध बिक्री पर शिकंजा

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 15 जनवरी

- दिल्ली में शराब गोदामों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी
- लाइसेंसधारी गोदामों पर लगे इन कैमरों के फुटेज चुनाव पूरा होने तक रखने के निर्देश

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए शराब गोदामों की सख्त निगरानी की जाएगी। इसके लिए दिल्ली आबकारी विभाग ने सभी आबकारी इंसपेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे इन गोदामों की निगरानी करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही दिल्ली में अवैध शराब की आपूर्ति शुरू हो गई थी।

दिल्ली आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग की विधानसभा चुनाव में शराब की अवैध बिक्री की आशंका पर पैनी नजर है। इस अवैध बिक्री को रोकने के लिए निर्धारित वेयरहाउस पर तैनात सभी आबकारी इंसपेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गोदामों पर शराब की कड़ी निगरानी करें और इसके लिए सुनिश्चित करें कि शराब गोदामों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे सही से चल रहे हैं। इंसपेक्टरों को इन कैमरों के सही संचालन का प्रमाणपत्र देने को भी कहा गया है। इसके अलावा आबकारी अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित लाइसेंसधारी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक गोदामों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बैकअप रखें।

दिल्ली में चुनाव के दौरान शराब की अवैध बिक्री लगातार बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा चुनाव की तैयारियों से पहले चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 1.55 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी, जबकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यह मात्रा 45,735 हजार लीटर थी।

इसी तरह वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 35,175 लीटर और 2013 के विधानसभा चुनाव में 32,503 लीटर अवैध शराब जब्त हुई थी। वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 33.38 लाख रुपये अवैध नकदी जब्त की गई थी, जबकि इस चुनाव में 13 जनवरी तक ही 53.38 लाख रुपये की अवैध नकदी जब्त की गई है।

चीनी के लिए दोहरी मूल्य नीति का सुझाव

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 15 जनवरी

कृषि जिंसों पर सरकार को सुझाव देने वाली एजेंसी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने केंद्र सरकार को देश में चीनी की बिक्री के लिए दोहरी मूल्य नीति तैयार करने का सुझाव दिया है। आयोग का मानना है कि इससे किसानों को फायदा होगा।

सीएसीपी के चेयरमैन विजय पॉल शर्मा ने कहा, 'आम उपभोक्ताओं के लिए वाजिब दाम के साथ ही औद्योगिक ग्राहकों के लिए उत्पादन लागत तथा उपलब्धता के आधार पर उच्च कीमत के लिए दोहरी मूल्य नीति बनाने पर विचार करने का यह उचित समय है।' देश में चीनी के कम उत्पादन के अनुमान और निर्यात की संभावनाओं में सुधार से थोक बाजार में चीनी के दाम 1 से 2 रुपये किलो तक बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी एम के मिल गेट दाम 33 से 34.50 रुपये किलो और महाराष्ट्र में चीनी एस के दाम 32 रुपये किलो हो गए हैं। सरकार ने देश भर में चीनी न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपये किलो तय किया है।

उद्योग के सूत्रों के अनुसार देश में कुल चीनी खपत का करीब 60 फीसदी हिस्सेदारी कंपनियों या बल्क में खरीद करने वाले ग्राहकों की है। इनमें शीतल पेय और मिठाई बनाने वाले भी शामिल हैं। इन ग्राहकों द्वारा सालाना 6 करोड़ टन चीनी की खपत होने का अनुमान है। आम ग्राहकों की हिस्सेदारी 40 फीसदी है। दिलचस्प है कि औद्योगिक खपत में लगातार तेजी आ रही है लेकिन घरेलू ग्राहकों की ओर से खपत में कमी आ रही है।

उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा, 'कंपनियों के लिए अधिक कीमत होने से चीनी मिलों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे वह गन्ने का बकाया तेजी से निपटाने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही किसानों को गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। किसानों के फायदे के लिए सभी तरह की पहल का हम समर्थन करते हैं।'

इस बीच रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान लगाया है कि चीनी के दाम औसतन 2 रुपये किलो बढ़ने से चीनी मिलों के मुनाफे में निकट अवधि में सुधार आ सकता है। दिसंबर अंत में चीनी के दाम नौ माह के उच्च स्तर पर थे। दूसरी ओर गन्ने की कीमत स्थिर बनी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इससे एसएपी और केंद्र द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य के बीच अंतर काफी कम हो गया है।

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ग्रुप हेड सब्यसाची मजूमदार ने कहा, 'चीनी के दाम बढ़ने और गन्ने की कीमत स्थिर रहने से चीनी मिलों के मुनाफे में निकट भविष्य में सुधार होगा।'

- सीएसीपी ने औद्योगिक और घरेलू ग्राहकों के लिए अलग-अलग कीमत पर विचार करने का दिया सुझाव
- शीतलपेय, आइसक्रीम और मिठाई बनाने वालों से वसूलें ज्यादा दाम
- इससे चीनी मिलों के साथ ही गन्ना किसानों को भी होगा लाभ

■ कंपनियों के लिए घरेलू ग्राहकों से **20** से **30** फीसदी ज्यादा कीमत रख सकती है सरकार

खबरों में रहे स्टॉक

विप्रो

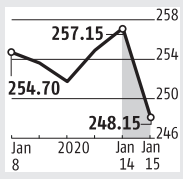

चौथी तिमाही में राजस्व अनुमान उम्मीद से कम

₹ 257.15 पिछला बंद भाव
₹ 248.15 आज का बंद भाव
▼ 3.50 %

चंबल फर्टिलाइजर्स ऐंड केमिकल्स

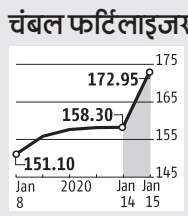

किसानों को सीधे तौर पर सब्सिडी के भुगतान की तैयारी

₹ 158.30 पिछला बंद भाव
₹ 172.95 आज का बंद भाव
▲ 9.25 %

बंधन बैंक

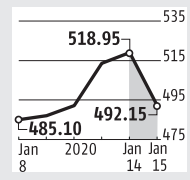

तीसरी तिमाही में मुनाफे के अतिरिक्त प्रावधान का झटका

₹ 518.95 पिछला बंद भाव
₹ 492.15 आज का बंद भाव
▼ 5.16 %

प्रेस्टिज एस्टेट प्रोजेक्ट्स

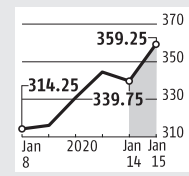

निफ्टी रियल्टी सूचकांक में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 339.75 पिछला बंद भाव
₹ 359.25 आज का बंद भाव
▲ 5.74 %

हीरो मोटोकॉर्प

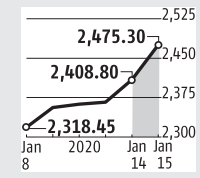

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 2,408.80 पिछला बंद भाव
₹ 2,475.30 आज का बंद भाव
▲ 2.76 %

संक्षेप में

सुंदरम फाइनैंस ने बेची इक्विफैक्स की हिस्सेदारी

सुंदरम फाइनैंस लिमिटेड ने इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की 10 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेच दी। कंपनी ने कहा कि 67.43 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 13.5 करोड़ शेयर बेचने के लिए शेयर खरीद समझौता लागू किया है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस मुहैया कराने वाली इक्विफैक्स का कारोबार वित्त वर्ष 2019 में 50.83 करोड़ रुपये रहा जबकि 31 मार्च 2019 को हैसियत 45.02 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2019 की सालाना रिपोर्ट में सुंदरम फाइनैंस ने इस कंपनी में अपने निवेश को लंबी अवधि का रणनीतिक निवेश बताया था। *बीएस*

फ्यूचर रिटेल ने जुटाए 50 करोड़ डॉलर

किशोर बियाणी की अगुवाई वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल ने डॉलर मूल्य वाले बॉन्डों के जरिये 50 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि यह भारत के खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र का पहला अंतरराष्ट्रीय बॉंड सौदा है। फ्यूचर रिटेल के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश बियाणी ने कहा, 'इससे हमें वित्तपोषण के स्रोतों के विविधीकरण में मदद मिलेगी। कंपनी इस धन का इस्तेमाल फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड से स्टोर खरीदने में किया जाएगा। इन प्रतिभूतियों को सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड (एसजीएक्स-एसटी) में सूचीबद्ध किया जाएगा।' *भाषा*

जेट एयरवेज को दो और प्रस्ताव मिले

सिनर्जी ग्रुप और प्रूडेंट एआरसी ने जेट के कायाकल्प के लिए सौंपी ईओआई

अनीश फडणीस और सुब्रत पांडा
मुंबई, 15 जनवरी

दक्षिण अमेरिका के सिनर्जी ग्रुप और दिल्ली स्थित प्रूडेंट एआरसी ने जेट के कायाकल्प के लिए ईओआई सौंपी हैं। ईओआई सौंपने की समय-सीमा बुधवार को समाप्त हो गई है।

सूत्रों का कहना है कि हिंदुजा समूह ने इस संकटग्रस्त एयरलाइन कंपनी में निवेश की संभावना तलाशी थी, लेकिन बाद में वह इससे पीछे हट गया। दुबई के एक फंड ने भी एयरलाइन में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उसने अपना प्रस्ताव नहीं सौंपा।

यह दूसरी बार है जब जेट के ऋणदाताओं ने ईओआई आमंत्रित की हैं, क्योंकि पहले दौर की बोली प्रक्रिया से एयरलाइन के कायाकल्प के लिए कोई समाधान योजना नहीं निकल सकी थी। ऋणदाताओं ने ईओआई सौंपने की समय-सीमा बढ़ाकर संभावित बोलीदाताओं को पर्याप्त समय दिया।

जेट एयरवेज का शेयर बुधवार को बीएसई पर लगातार 12वें दर 5 प्रतिशत के अपर सकिट के साथ 50.25 रुपये पर बंद हुआ। शेयर 18 जुलाई, 2019 से अपने ऊंचे स्तरों पर कारोबार कर रहा है। बुधवार की तेजी के साथ जेट एयरवेज की शेयर कीमत 22 अक्टूबर 2019 के निचले स्तर (15.10 रुपये) से तीन महीने से भी कम समय में तीन गुना (233 प्रतिशत) तक बढ़ी है।

सिनर्जी ग्रुप का कहना है कि लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डों पर उपलब्ध स्लॉट एयरलाइन परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और वह तभी जेट की समाधान प्रक्रिया में हिस्सा लेगा जब इन स्लॉट को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाए। समूह ने एयरलाइन के कायाकल्प के लिए कई अन्य शर्तें भी रखी हैं। वह चाहता है कि उसकी परिसंपत्तियों, कर्मचारियों और परिचालन परमिट के साथ एक नई कंपनी बनाई जाए, लेकिन इस सौदे में देनदारियां शामिल न हों। अभी तक सिनर्जी ग्रुप को ऐसा भारतीय भागीदार नहीं मिला है जो एयरलाइन का बड़ा नियंत्रण संभाल सके। सरकारी मानकों के तहत एयरलाइन में विदेशी निवेश 49 प्रतिशत पर सीमित है।

उधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि वह एक मजबूत बिजनेस प्लान सौंपे जाने पर जेट एयरवेज के लिए घरेलू स्लॉट लौटाने का निर्णय लेगा। जेट के मुख्य रणनीतिक अधिकारी राजेश प्रसाद ने कहा है कि दिवालिया प्रक्रिया के तहत एयरलाइन में निवेश आकर्षक होगा। जेट एयरवेज ने 17 अप्रैल को अपना परिचालन बंद कर दिया था और जून में उसे दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया। एयरलाइन की बिक्री के लिए दो बार ईओआई आमंत्रित किए गए और बोलियां सौंपने की समय-सीमा भी बढ़ाई गई, लेकिन अभी खरीदारों की ओर से कोई समाधान योजना पेश नहीं की गई है।

जेट एयरवेज के संभावित मालिक को एयरलाइन का ब्रांड, उसके लॉयल्टी व्यवसाय में 49.9 प्रतिशत हिस्सेदारी और 12 विमान मिलेंगे, लेकिन हवाई अड्डा स्लॉटों को लेकर अभी अनिश्चितता है। मजबूत निवेशक नहीं मिल पाने से इस एयरलाइन के कायाकल्प की राह में समस्या बनी हुई है।

मौजूदा समय में, एयरलाइन के 12 विमान हैं जिनमें तीन बोइंग 737, 6 बोइंग 777 और तीन एयरबस ए330 (एक विमान एयर सर्बिया को पट्टे पर दिया गया है) शामिल हैं। इनमें से तीन बोइंग 737 विमान पूरी तरह एयरलाइन के स्वामित्व वाले हैं।

पुनरुद्धार की योजना

- सिनर्जी ग्रुप का कहना है कि लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डों पर उपलब्ध स्लॉट एयरलाइन परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं
- जेट एयरवेज के संभावित मालिक को एयरलाइन का ब्रांड, उसके लॉयल्टी व्यवसाय में 49.9 प्रतिशत हिस्सेदारी और 12 विमान मिलेंगे, लेकिन हवाई अड्डा स्लॉटों को लेकर अभी अनिश्चितता है

चुनौतीपूर्ण होगा अगला वित्त वर्ष: एचएमएसआई

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 15 जनवरी

होंडा मोटरसाइकिल ऐंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) को निकट भविष्य में दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कंपनी ने उम्मीद जताई है कि त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री में सुधार दिख सकता है।

एचएमएसआई ने आज अपने प्रमुख स्कूटर ब्रांड ऐक्टिवा के 6जी संस्करण को लॉन्च किया। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 63,912 रुपये होगी और इस मॉडल की आपूर्ति फरवरी से शुरू होगी। ऐक्टिवा 6जी अपने मौजूदा मॉडल के मुकाबले 12 से 13 फीसदी महंगा होगा।

होंडा के 110 सीसी एकल सिलिंडर इंजन के साथ ऐक्टिवा का नया मॉडल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से लैस होगा। बीएस6 उत्सर्जन मानदंडों के तहत इस प्रौद्योगिकी के कारण उत्पाद की कीमत बढ़ गई है। भारत में एचएमएसआई की कुल बिक्री में स्कूटर का योगदान 65 फीसदी से अधिक है।

एचएमएसआई के अध्यक्ष, सीईओ और प्रबंध निदेशक मिनोरू कातो ने दूसरे सबसे बड़े दोपहिया बाजार के लिए परिदृश्य को उथल-पुथल भरा बताते हुए सतर्क रुख अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बीएस6 उत्सर्जन मानदंडों के लागू होने से वाहन बाजार में उथल-पुथल मचने की आशंका है।

कातो ने कहा, 'हमारा मानना है कि बाजार दोबारा बढ़त दर्ज करेगी। लेकिन अगला वित्त वर्ष (2020-21) मूल्य के मोर्चे पर कहीं अधिक कठिन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ग्राहकों द्वारा नई कीमतों को स्वीकार किए जाने के पांच से छह महीने बाद स्थिति में सुधार होगा। दीवाली के दौरान बिक्री में तेजी आ सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि वह पिछले साल जैसी रहेगी।'

नए उत्सर्जन मानदंड 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इससे दोपहिया वाहनों की कीमतों में 10 से 14 फीसदी की बढ़ोतरी होने के आसार हैं जो इंजन के आकार पर निर्भर करेगी। यह ऐसे समय में हो रहा है जब कुल मिलाकर वाहन बाजार दो दशक की सबसे लंबी मंदी से जूझ रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में एचएमएसआई की बिक्री एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 16 फीसदी घटकर 37 लाख वाहन रह गई है।

ओएसपीआईएल के समाधान को झटका

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 15 जनवरी

ओडिशा स्लरी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ओएसपीआईएल) के समाधान में एक नई परेशानी सामने आई है। लेनदारों की समिति की तरफ से मंजूर आर्सेलरमित्तल की समाधान योजना को नाकाम समाधान आवेदकों त्रिवेणी अर्थमूवर्स और श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस ने चुनौती दी है।

आर्सेलरमित्तल के प्रवक्ता ने कहा, हम कानूनी मसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी पुष्टि करते हैं कि ओडिशा स्लरी पापलाइन के लेनदारों ने आर्सेलरमित्तल की योजना को आमसहमति से मंजूरी दी थी और 100 फीसदी मतदान योजना के हक में हुआ था। इस योजना के तहत सभी लेनदारों के मूलधन की पूरी रकम का अग्रिम भुगतान होना है।

दिसंबर में ओएसपीआईएल की लेनदारों की समिति ने आर्सेलरमित्तल की 2,200 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की पेशकश को मंजूरी दी थी।

शुक्रवार को होगी बियाणी और बेजोस की बैठक

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 15 जनवरी

व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के विरोध-प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को मुंबई में फ्यूचर ग्रुप के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) किशोर बियाणी और एमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की बैठक होने जा रही है। गुरुवार को एमेजॉन के संभव कार्यक्रम में बियाणी मुख्य वक्ता होंगे जबकि शुक्रवार को होने वाली उनकी आमने-सामने की बैठक को काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उस दौरान दोनों कारोबारी भविष्य की साझेदारी की रूपरेखा तैयार करेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। बैठक के दौरान ऑनलाइन भुगतान में करार पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों कंपनियां अपनी साझेदारी के दूसरे चरण में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकती हैं। पहले चरण के तहत एमेजॉन फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के लिए ऑनलाइन बिक्री साझेदार बनी थी। दूसरी ओर बिग बाजार एमेजॉन प्राइम ग्राहकों के लिए डिलिवरी साझेदार बनी थी। दोनों कंपनियां पहले से ही अपने डिजिटल वॉलेट- एमेजॉन पे और फ्यूचर पे- का संचालन कर रही हैं। इस मामले से अवगत सूत्रों ने बताया कि अब दोनों कंपनियां इस क्षेत्र में तालमेल बिठाने की संभावनाएं तलाश रही हैं।

आम्रपाली मामले में बढ़ी जेपी मॉर्गन की मुश्किलें

पृष्ठ 1 का शेष...

जेपी मॉर्गन से आम्रपाली जोडिएक के शेयर नीलकंठ बिल्डक्राफ्ट और रुद्राक्ष इंट्रासिटी ने 140 करोड़ रुपये में खरीदे। इन मुखौटा कंपनियों के मालिक आम्रपाली के एक अधिकारी से जुड़े हैं। इनमें से एक उनका चपरासी और दूसरा ऑफिस बॉय है। इस बारे में जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'जेपी मॉर्गन उच्चतम न्यायालय में चल रही कार्यवाही में पक्ष नहीं है और उसे न्यायालय की तरफ से कोई पत्र नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि खबरों का संबंध विदेशी रियल एस्टेट फंडों द्वारा निवेश करने और उसे निकालने से है। जेपी मॉर्गन में हम कानूनों, नियमों और नीतियों का पूरी तरह पालन करने में विश्वास रखते हैं।' सूत्रों ने कहा कि ईडी ने जेपी मॉर्गन के पूर्व नामांकित निदेशकों से भी पूछताछ की है जो आम्रपाली जोडिएक और आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के निदेशक मंडल में शामिल थे। अगर जरूरत पड़ी तो जांच की आंच इस विदेशी कंपनी के और अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है। फेमा जांच के दौरान डेवलपरों ने कहा था कि जेपी मॉर्गन और आम्रपाली समूह के बीच हुए शेयर सबस्क्रिप्शन समझौते के कारण शेयर की कीमत में भारी उछाल आई थी।

एयरटेल का क्यूआईपी हुआ पूरा

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 15 जनवरी

भारती एयरटेल ने पात्र संस्थागत खरीदारों को 32.35 करोड़ इक्विटी शेयर का आवंटन 445 रुपये प्रति शेयर पर करने का ऐलान किया। कंपनी पात्र संस्थागत नियोजन के जरिए 2 अरब डॉलर (14,000 करोड़ रुपये) जुटा रही है और यह पेशकश मंगलवार को बंद हुई।

इश्यू की कीमत फ्लोर प्राइस 452.09 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले 1.57 फीसदी कम है। रकम जुटाने की यह कवायद मुख्य रूप से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की देनदारी के भुगतान के लिए हुई है।

इस कवायद से मिली रकम का इस्तेमाल प्राथमिक तौर पर कंपनी के लंबी अवधि के संसाधन और बैलेंस शीट की मजबूती, अल्पावधि व लंबी अवधि के कर्ज के भुगतान, पूंजीगत खर्च, सांविधिक बकाया, लंबी अवधि की कार्यशील पूंजी की जरूरत और कंपनी के सामान्य कामकाज पर होगा, जिसकी इजाजत कानून के तहत है। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

भारती एंटरप्राइजेज के समूह निदेशक हरजीत कोहली ने कहा, बाजार में उतारचढ़ाव के माहौल और चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद इस पेशकश को वैश्विक व देसी निवेशक समुदाय से अच्छी व मजबूत प्रतिक्रिया मिली। यह एयरटेल के बढ़त केंद्रित वित्तीय प्रदर्शन और हमारे कारोबार में भविष्य में बढ़त की संभावना को रेखांकित करता है।

भारती एयरटेल को अतिरिक्त सांविधिक देनदारी के तौर पर करीब 35,586 करोड़ रुपये चुकाने हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में दूरसंचार कंपनियों की एजीआर देनदारी पर फैसला दिया था।

इस महीने भारती एयरटेल के शेयरधारकों ने इक्विटी के जरिए 2 अरब डॉलर और कर्ज के जरिए 1 अरब डॉलर जुटाने की मंजूरी दी है।

एयरटेल ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) बंद करने की घोषणा की और इश्यू की कीमत 445 रुपये प्रति शेयर तय कर दिया जो फ्लोर प्राइस 452.09 रुपये के मुकाबले 1.57 फीसदी कम है।

कंपनी ने कहा, पात्र संस्थागत खरीदारों को 32.35 करोड़ इक्विटी शेयरों का आवंटन होगा। रकम जुटाने की कवायद के लिए निदेशकों की विशेष समिति ने भी इश्यू प्राइस समेत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी) की शर्तों को मंजूरी दे दी।

नियामकीय सूचना में कहा गया है, साल 2025 में भुगतान वाला एफसीसीबी कंपनी के 5 रुपये वाले पूर्ण चुकता शेयरों में परिवर्तित होंगे, जिसका भाव 534 रुपये प्रति शेयर होगा।

ऐक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जे पी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वैश्विक संयोजक और बुकरनिंग लीड मैनेजर की भूमिका निभाई जबकि गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, डीएसपी मेरिल लिंच लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचएसबीसी सिक्योरिटीज ऐंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्यूआईपी इश्यू के लिए बुकरगिं लीड मैनेजर थे।

कंपनी ने कहा, एफसीसीबी की पेशकश ने तीन साल बाद भारतीय एफसीसीबी बाजार को दोबारा खोल दिया है।

भारती एयरटेल ने जुटाई रकम

- एयरटेल ने पात्र संस्थागत खरीदारों को 32.35 करोड़ इक्विटी शेयर का आवंटन 445 रुपये प्रति शेयर पर करने का ऐलान किया
- कंपनी पात्र संस्थागत नियोजन के जरिए 2 अरब डॉलर (14,000 करोड़ रुपये) जुटा रही है और यह पेशकश मंगलवार को बंद हुई
- इश्यू की कीमत फ्लोर प्राइस 452.09 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले 1.57 फीसदी कम है
- रकम जुटाने की यह कवायद मुख्य रूप से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की देनदारी के भुगतान के लिए हुई है

बिड़ला की कंपनियां विदेश से जुटाएंगी 3.1 अरब डॉलर

देव चटर्जी
मुंबई, 15 जनवरी

बिड़ला समूह की कंपनियां नोवेलिस (हिंडाल्को की सहायक) और एसकेआई कार्बन ब्लैक मॉरीशस 3.1 अरब डॉलर का कर्ज जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतर रही हैं।

एक ओर जहां नोवेलिस पिछले कर्ज के मुकाबले कम दर पर 1.6 अरब डॉलर जुटा रही है, वहीं एसकेआई कार्बन ब्लैक ने बॉन्डों की बिक्री के जरिए 1.5 अरब डॉलर जुटाने के लिए 16 बैकों का सहयोग ले रही है।

एसकेआई कार्बन ब्लैक क स्वामित्व प्रवर्तकों के पास है और पिछले साल जून में वोडाफोन आइडिया के राइट्स इश्यू में निवेश किया था। कंपनी की योजना इस रकम का इस्तेमाल पुराने कर्ज के निपटान और कंपनी के सामान्य कामकाज में करने का है। बैंकरों ने यह जानकारी दी। बैंकरों ने कहा, एक अन्य अमेरिकी कंपनी एलेरिस कॉर्प का अधिग्रहण 3 अरब डॉलर में करने में जुटी नोवेलिस को यह कर्ज पिछले कर्ज के मुकाबले कम से कम 200 आधार अंक कम पर मिलेगा और इस तरह से कंपनी की वित्तीय लागत में काफी बचत होगी। बैंकरों ने कहा, अगर विकट परिस्थिति में एलेरिस का अधिग्रहण समझौता रद्द होता है तो 12 महीने की अवधि में नोवेलिस 40 करोड़ डॉलर का बॉन्ड इश्यू प्राइस पर वापस कर सकती है।

एलेरिस के अधिग्रहण मामले में अभी अमेरिकी सरकारों की मंजूरी की प्रतीक्षा हो रही है जबकि यूरोपीय आयोग और चीन की सरकार इस सौदे को मंजूरी दे चुकी है। यूरोपीय मंजूरी बेल्जियम में एलेरिस के संयंत्र के लिए है, जो ऑटोमोटिव व स्पेशियलिटी बाजारों के लिए एल्युमीनियम बनाती है।

पुराने कर्ज के निपटान के लिए नोवेलिस, एसकेआई कार्बन कम दर पर लेगी कर्ज

कंपनी इस सौदे को पूरा करने की 21 जनवरी 2020 की समयसीमा में चूक कर सकती है और बैंकरों को कहना है कि इसकी तारीख बढ़ाई जा सकती है।

बिड़ला समूह की तरफ से रकम जुटाने का काम भारती एयरटेल की तरफ से विदेशी निवेशकों को बॉन्डों व शेयरों की बिक्री के जरिए 3 अरब डॉलर जुटाए जाने के कुछ ही दिनों के भीतर हो रहा है।

बैंकरों ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद विदेशी निवेशकों का नजरिया भारत को लेकर तेजी का है, जो अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों की तरफ से कर्ज व शेयर बिक्री को लेकर उनकी प्रतिक्रिया में नजर आता है। एक बैंकर ने कहा, हालांकि यह उत्साह भविष्य में भी बना रहता है या नहीं यह देसी व वैश्विक उतारचढ़ाव के अलावा आगामी बजट में सरकारी सुधार पर भी निर्भर करेगा। कैलेंडर वर्ष 2019 में भारतीय कंपनियों ने डॉलर बॉन्ड के जरिए 23.6 अरब डॉलर जुटाए, जो साल 2018 के मुकाबले पांच गुना ज्यादा है।

सेबी के आदेश के खिलाफ सैट पहुंचा ऐक्सिस बैंक

जश कृपलानी
मुंबई, 15 जनवरी

ऐक्सिस बैंक ने बुधवार को सेबी के आदेश के खिलाफ यथास्थिति की मांग करते हुए प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) का दरवाजा खटखटाया। सेबी ने कहा था कि जिन क्लाइंटों के ऊपर कार्वी का बकाया नहीं है उनके शेयर गिरवी रखना कानूनी रूप से अवैध है।

पंचाट ने ऐक्सिस बैंक को इस वास्तविकता के आलोक में अंतरिम राहत दी कि विगत में नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी ने कार्वी मामले में सेबी के नवंबर 2019 के आदेश के आधार पर क्लाइंटों की प्रतिभूतियां वापस हस्तांतरित कर दी थी। इसकी पुष्टि करते हुए ऐक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा, बैंक ने सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में अपील की है। सैट ने बुधवार को यथास्थिति बरकार रखते हुए अगली सुनवाई तक सेबी के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत दी। सेबी ने अपने आदेश में 171.74 करोड़ रुपये के शेयरों की पहचान की थी जहां क्लाइंटों ने पूरा बकाया चुका दिया है। ऐक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा, हमारा कहना है कि ये शेयर कर्ज से मुक्त हैं और आंकड़े की दोबारा जांच की जानी चाहिए।

अपने आदेश में सेबी ने कहा है कि कार्वी की तरफ से ऐक्सिस बैंक के पास गिरवी रखे गए 13.69 करोड़ रुपये के क्लाइंटों के शेयरों का हस्तांतरण तब हो सकता है जब बैंक हर क्लाइंट की तरफ से इसके लिए अधिकृत किए जाने का सबूत पेश करे। नियामक ने पाया कि जिन क्लाइंटों के ऊपर बकाया नहीं है उसके शेयर को गिरवी रखना कानूनी तौर पर वैध नहीं है। इन प्रतिभूतियों की कीमत 171.74 करोड़ रुपये है। सेबी ने आदेश में कहा, अगर ऐक्सिस बैंक 13.69 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के लिए क्लाइंटों की तरफ से अधिकृत किए जाने का सबूत पेश करता है तो ऐसी प्रतिभूतियां जारी की जा सकती हैं, लेकिन इससे पहले एनएसई की निगरानी में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करना होगा।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत बरुआ ने भी पाया कि क्लाइंटों की प्रतिभूतियां पाने के लिए हर क्लाइंट से अधिकृत किए जाने का सबूत लाना होगा और ऐसे गिरवी के लिए क्लाइंटों की पावर ऑफ अटॉर्नी पर्याप्त नहीं होगा। ऐक्सिस बैंक ने अपनी दलील में कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी अधिकृत किए जाने का पर्याप्त सबूत है। ऐक्सिस बैंक ने इन शेयरों के बदले कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी थी।

म्युचुअल फंड के आवेदन को मंजूरी नहीं : सेबी ने म्युचुअल फंड लाइसेंस के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के आवेदन पर मंजूरी नहीं दी है। नियामक की रिपोर्ट बताती है कि लंबित नियामकीय कदम को देखते हुए कार्वी का आवेदन अभी रोक लिया गया है। कार्वी ने पिछले साल फरवरी में म्युचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन किया था। उधर, म्युचुअल फंड वितरक एनजे इंडिया इन्वेस्ट को म्युचुअल फंड कारोबार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई।

भारती के इश्यू से रकम जुटाने से साल 2020 का परिदृश्य हुआ मजबूत

समी मोडक
मुंबई, 15 जनवरी

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की 2 अरब डॉलर जुटाने की कवायद ने साल 2020 के लिए इक्विटी के जरिए रकम जुटाने का परिदृश्य मजबूत बना दिया है, खास तौर से पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिए। द्वितीयक बाजार में व्यापक तेजी को देखते हुए बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय कंपनी जगत पिछले साल के मुकाबले इस साल क्यूआईपी, ब्लॉक डील आदि के जरिए ज्यादा रकम जुटाएगा। पिछले कैलेंडर वर्ष में एक दर्जन कंपनियों ने अपनी कारोबारी जरूरतें पूरी करने के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपये जुटाए, जो साल 2018 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है।

इस साल भारती एयरटेल ने 14,400 करोड़ रुपये का क्यूआईपी पूरा किया, वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स और कुछ वित्तीय फर्में इस वित्त वर्ष के आखिर तक शेयर बिक्री का काम पूरा करने का इरादा जता रही हैं। हालिया क्यूआईपी के प्रदर्शन से उत्साहित और शेयर बाजार की रफ्तार इश्यू करने वालों व बैंकरों को बड़े सौदे पेश करने का आत्मविश्वास दे रहे हैं। यह कहना है उद्योग की कंपनियों का। दूसरी ओर कई बड़े देसी व वैश्विक निवेशक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों में निवेश की इच्छा जता रहे हैं।

खेतान ऐंड कंपनी के कार्यकारी निदेशक सुधीर बस्सी ने कहा, पूंजी जुटाने के लिहाज से यह साल निश्चित तौर पर अच्छा होगा। पहले ही हम पिछले महीनों में तेजी देख चुके हैं। हमारा मानना है कि क्यूआईपी रकम जुटाने का तरजीही जरिया बन सकता है। लार्जकैप व चुनिंदा मिडकैप की अच्छी मांग होगी। चूंकि बाजार की तेजी व्यापक है, लिहाजा हम नई प्रतिभूतियों में निवेश में और सुधार देखेंगे।

इस साल वैश्विक स्तर पर ज्यादातर बाजारों (अमेरिका व भारत समेत) में जोखिम उठाने के मामले में अनुकूलता दिखी है और यह नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आर्थिक माहौल साल की बाकी अवधि के लिहाज से इक्विटी के लिए सहायक दिख रहा है। पिछले साल के उलट बाजार की तेजी सिर्फ लार्जकैप तक सीमित नहीं रही है। इस साल अब तक एनएसई मिडकैप और एनएसई स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमश: 4.3 फीसदी और 6.8 फीसदी चढ़े हैं। इसकी तुलना में बेंचमार्क निफ्टी में महज 1.4 फीसदी की तेजी आई है।

कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इक्विटी कैपिटल मार्केट्स प्रमुख वी जयशंकर का अनुमान है कि क्यूआईपी व ब्लॉक डील के जरिए साल 2020 में करीब 30 फीसदी रकम जुटाई जाएगी। उन्होंने कहा, संस्थागत निवेशकों के लिए क्यूआईपी और ब्लॉक डील किसी कंपनी का ज्यादा शेयर अधिग्रहीत करने का मौका देता है। सामान्य तौर पर द्वितीयक बाजार में इतने शेयर की खरीद मुश्किल होती है। ये बातें उन्होंने हाल में रकम जुटाने के एक कार्यक्रम में कही थी। रकम जुटाने की कवायद को व्यापक आर्थिक लिहाज से अच्छे संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि इक्विटी पूंजी तक पहुंच कंपनियों को विस्तार योजना का खाका खींचने का आत्मविश्वास देगा, जो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लाभकारी होगा।

ब्लैकरॉक का निवेश घटने से देसी फर्मों को मिलेगी चुनौती

ज्योति मुकुल और श्रेया जय
नई दिल्ली, 15 जनवरी

दुनिया की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक ब्लैकरॉक ने घोषणा की है कि वह उन कंपनियों से अपना निवेश निकालेगी जो अपने कुल राजस्व का 25 प्रतिशत हिस्सा ताप कोयला उत्पादन से प्राप्त करती हैं। इससे भविष्य में इन कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किए जाने से एनटीपीसी, अदाणी समूह और कोल इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों के लिए निवेशकों का आकार सिकुड़ सकता है।

ब्लैकरॉक की 19 सदस्यीय ग्लोबल एक्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने ग्राहकों को भेजे पत्र में कहा है, 'हम उन कंपनियों की प्रतिभूतियों (डेट और इक्विटी दोनों) के अपने निवेश पोर्टफोलियो से बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं, जो ताप कोयला उत्पादन से अपना 25 प्रतिशत राजस्व हासिल करती हैं। 2020 के मध्य तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।'

ब्लैकरॉक ने कहा है कि ज्यादा पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) जोखिम वाले क्षेत्रों के मूल्यांकन के तौर पर वह उन अन्य व्यवसायों की समीक्षा करेगी जो उत्पाद के तौर पर ताप कोयले पर ज्यादा निर्भर हैं। इस श्रेणी में एनटीपीसी और अदाणी पावर जैसी ताप विद्युत उत्पादकों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, ब्लैकरॉक के वैकल्पिक व्यवसाय भी इन कंपनियों में भविष्य में प्रत्यक्ष रूप से निवेश नहीं करेंगे।

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकनोमिक्स ऐंड फाइनैंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घोषणा का मतलब यह हो सकता है कि चाइना शेन्हुआ, चाइना नैशनल कोल ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड, अदाणी एंटरप्राइजेज, आदि समीक्षा कर सकती हैं और उनमें निवेश घट सकता है।

एलऐंडटी इन्फोटेक का राजस्व बढ़ा : मध्यम आकार की आईटी सेवा कंपनी एलऐंडटी इन्फोटेक ने बड़े सौदों की पृष्ठभूमि में राजस्व में दो अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की है, वहीं कंपनी का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में मामूली बढ़ा। आईटी कंपनी का शुद्ध लाभ तिमाही में 376.7 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले मामूली ज्यादा है। कंपनी का राजस्व 13.7 फीसदी बढ़कर 2,811 करोड़ रुपये रहा। *बीएस*

'स्वत: ऑनलाइन सुविधा बंद करें बैंक'

अनूप रॉय
मुंबई, 15 जनवरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज बैंकों से कहा कि जारी किए जाने वाले किसी भी नए कार्ड को भारत में केवल भौतिक इस्तेमाल जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के लिए सक्षम होना चाहिए। कार्ड पर इंटरनेट और अन्य सुविधाएं केवल तभी दी जानी चाहिए जब ग्राहक उसके लिए विशेष तौर पर अनुरोध करे।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहक के पास भौतिक और इंटरनेट इस्तेमाल के लिए किसी भी तरह की लेनदेन में राशि की सीमा निर्धारित करने का विकल्प होना चाहिए।

मौजूदा कार्डों के लिए बैंक अपने विवेक के आधार पर तय कर सकते हैं कि उन्हें ग्राहकों को कार्ड पर इंटरनेट इस्तेमाल की सुविधा देनी है अथवा नहीं। लेकिन ऐसे कार्ड जिनका इस्तेमाल कभी भी ऑनलाइन लेनदेन के लिए नहीं किया गया है या किसी भी तरह से कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन सुविधाओं को स्वत: बंद कर दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कार्ड जिनका इस्तेमाल कभी भी इंटरनेट लेनदेनों के लिए नहीं किया गया है आगे से ऑनलाइन लेनदेनों के लिए भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

धोखाधड़ी रोकने का प्रयास

बैंकों के ये सुविधाएं विभिन्न माध्यमों के लिए चौबीसों घंटे दी जानी चाहिए

- जारी किए जाने वाले/पुनः जारी किए जाने वाले सभी कार्ड का इस्तेमाल केवल भौतिक इस्तेमाल के लिए हो सकता है
- जोखिम धारणा के आधार पर बैंक मौजूदा कार्डों में इंटरनेट की सुविधा बंद कर सकते हैं
- ग्राहक को लेनदेन चालू रखने या बंद करने और लेनदेन की सीमा तय करने में सक्षम हों
- कार्ड की स्थिति में कोई बदलाव होने पर बैंक एसएमएस और ई-मेल के जरिये ग्राहक को अलर्ट, ताजा जानकारी भेजें

रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक अधिसूचना में कहा, 'मौजूदा कार्डों के लिए जारीकर्ता अपने जोखिम धारणा के आधार पर यह निर्णय ले सकता है कि कार्ड में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों की सुविधा नहीं है, कार्ड में अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों की सुविधा है और कार्ड के संपर्क रहित लेनदेन के अधिकारों को निष्क्रिय किया जाए अथवा नहीं। ऐसे मौजूदा कार्ड जिनका इस्तेमाल कभी ऑनलाइन (कार्ड में सुविधा नहीं है)/ अंतरराष्ट्रीय /संपर्क रहित लेनदेन के लिए नहीं हुआ है उनको इस उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से निष्क्रिय किया जाएगा।'

जब कोई बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जारी करता है तब वह इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं भी देता है। हालांकि, जो लोग इस तरह के लेनदेन में खुद को सहज नहीं पाते हैं आसानी से कॉल सेंटर के जरिये हो रही घोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी में धोखेबाज व्यक्ति कॉल कर कार्ड की सारी जानकारी और फोन पर आए ओटीपी मांग लेता है और कार्डधारक का पैसा उड़ा लेता है।

इसलिए रिजर्व बैंक मानता है कि जो लोग पहले से ऑनलाइन लेनदेन कर रहे हैं वे सीवीवी संख्या या ओटीपी के महत्त्व को समझते हैं और फोन पर इसकी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। लिहाजा ऐसे लोग इन सुविधाओं का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट से जुड़े धोखाधड़ी को लेकर जागरूक नहीं रहने वाले लोग आगे भी इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि उनके कार्ड पर यह सुविधा आगे से स्वत: उपलब्ध नहीं रहेगी।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी कहा है कि सभी कार्डधारकों को लेनदेन शुरू करने/ बंद करने और उसकी सीमा तय करने व उसे बढ़ाने या घटाने जो कि कार्ड की सीमा के भीतर होगी जिसे जारीकर्ता ने निर्धारित किया हो, मुहैया कराई जाए। यह सुविधा सभी तरह के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, पीओएस/ एटीएम/ ऑनलाइन लेनदेनों/ संपर्क रहित लेनदेनों में दी जानी चाहिए।

ये सुविधाएं सभी तरह के माध्यमों जैसे मोबाइल एप्लीकेशन /इंटरनेट बैंकिंग /एटीएम /इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (आईवीआर) पर 24 घंटे दी जानी चाहिए और इन्हें शाखाओं के जरिये भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि कार्ड की स्थिति में कोई बदलाव होने की सूरत में बैंकों को एसएमएस और ई-मेल के जरिये ग्राहक को अलर्ट, ताजा जानकारी, स्थिति आदि भेजना चाहिए।

30 फीसदी बढ़ेगा रेलवे कोच विनिर्माण

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 15 जनवरी

भारतीय रेलवे की कोच विनिर्माण इकाइयों के उत्पादन 2019-20 में 30 प्रतिशत बढ़कर करीब 8,000 कोच रहने की संभावना है। साथ ही 2020-21 में इसमें 25 प्रतिशत और बढ़ोतरी की संभावना है।

भारत अब कोच, ट्रेनसेट, पहियों और अन्य संबंधित सामान का निर्यात एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के देशों में करने की तैयारी कर रहा है।

आज रेलवे बोर्ड में सदस्य (रोलिंग स्टॉक) राजेश अग्रवाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, 'इस समय हमारा निर्यात कम है और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों तक सीमित है। अब उत्तर अमेरिका जैसे देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

उत्तर अमेरिका में हम पहले पहिए व अन्य सहायक सामग्री का निर्यात कर शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके बाद कोच और ट्रेनसेट का निर्यात करेंगे।'

रेलवे की सभी विनिर्माण इकाइयों ने 2018-19 में करीब 6,000 कोच बनाए हैं, जो अब बढ़कर करीब 8,000 होने की संभावना है।

अग्रवाल ने कहा कि व्हील फैक्टरियों के काम में भी पिछले एक साल में तेज विस्तार हुआ है।

भारतीय रेल ने माल ढुलाई क्षमता मौजूदा एक अरब टन से बढ़ाकर अगले 4-5 साल में 2 अरब टन करने का लक्ष्य रखा है। भारत में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी महज 20 से 25 प्रतिशत है, जिसे करीब 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

नई रणनीति

- एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका को निर्यात पर ध्यान दे रहा रेलवे
- अगले वित्त वर्ष में रेल कोच विनिर्माण में 25 प्रतिशत और बढ़ोतरी की संभावना
- माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी बढ़ाने की की दिशा में हो रहा काम

उन्होंने कहा, 'भारत में कुल 4-5 अरब टन माल ढुलाई होती है। हमने यथासंभव इसमें रेलवे की हिस्सेदारी अधिकतम करने का लक्ष्य रखा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। हमारी योजना माल ढुलाई की लागत 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करने की है।'

लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी पूर्वी व पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे के चालू होने और ऑटोमोबाइल उद्योग सहित खास ग्राहकों के लिए वैगन की नई डिजाइन से आएगी।

उन्होंने कहा कि कुल माल ढुलाई में कोयले की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत है, जो कम होने की संभावना है, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर रेलवे बड़ा दाव लगा रहा है।

उन्होंने कहा, 'अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में रेलवे की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी कम है। कुल 40 लाख वाहनों की ढुलाई होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में बड़ी क्षमता है।'

रेलवे सभी कार और दोपहिया विनिर्माताओं से इस सिलसिले में बात कर रहा है। मारुति सुजूकी (एमएसआईएल) ने हाल ही में कहा था कि वह 2030 तक अपनी आधी कारों की ढुलाई रेलवे से कराने को इच्छुक है।

कंपनी ने रेल से 2018-19 में महज 5 लाख कार की ढुलाई कराई है।

अन्य श्रेणी के आयात पर अंकुश लगाएगी सरकार

भाषा
नई दिल्ली, 15 जनवरी

सरकार माल की अन्य श्रेणी में आयात में तेज बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ऐसे आयातकों से 30 दिन के भीतर विदेश व्यापार कार्यालय से एचएसएन या शुल्क कोड हासिल करने को कहा है।

गोयल ने कहा कि यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो सरकार उनके आयात पर कड़े अंकुश लगाएगी।

व्यापार की बोली में प्रत्येक उत्पाद को एचएसएन कोड (हार्मोनाइज्ड सिस्टम आफ नोमन्क्लेचर) में वर्गीकृत किया जाता है। इससे दुनिया भर में वस्तुओं के प्रणालीगत वर्गीकरण में मदद मिलती है। गोयल ने कहा कि देश के आयात में अन्य की श्रेणी की वजह से दिक्कत आ रही है।

उन्होंने कहा कि अन्य के नाम पर तमाम तरह का सामान देश में मंगाया जा रहा है। उन्होंने एक विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि देश में आयातित चार में से एक उत्पाद अन्य श्रेणी का होता है।

वित्त वर्ष 2018-19 में देश के कुल 500 अरब डॉलर के आयात में से 100 अरब डॉलर का आयात अन्य श्रेणी में हुआ। गोयल ने कहा, 'मैं इस बारे में जर्मनी का मॉडल अपनाऊंगा। उन्होंने कहा कि वह इस पर आयातकों की प्रतिक्रिया का 30 दिन तक इंतजार करेंगे। उसके बाद इस श्रेणी में किसी भी तरह के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।'

उन्होंने कहा कि आयातकों को इस तरह के आयात के लिए मंत्रालय से विशेष लाइसेंस लेना होगा। इसके बिना आप अन्य श्रेणी में कोई सामान आयात नहीं कर सकेंगे।

गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के राष्ट्रीय मानक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'आज मैं इस बारे में अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं।

मैं ऐसे सामान का आयात करने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने उत्पादन को संबंधित एचएसएन कोड में वर्गीकृत कराएं।'

गोयल ने आयातकों से कहा कि वे अपनी नजदीकी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से संपर्क करें।

रिफंड के लिए अब नहीं करना होगा 7 दिन इंतजार

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 15 जनवरी

अगली बार जब आप हवाईयात्रा का टिकट या ई-कॉमर्स का ऑर्डर रद्द करेगे तो आपको पैसे वापस पाने के लिए 5-7 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

बेंगलूरु की कंपनी रेजरपे ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जिससे ई-कॉमर्स, ट्रैवल और फूडटेक उद्योगों से जुड़ा कम से कम 30 प्रतिशत रिफंड तत्काल हो जाएगा, जो ग्राहक ने उड़ान रद्द होने और गुणवत्ता से जुड़ी वजहों से ऑर्डर वापस किया है।

ग्राहकों के लिए ऑनलाइन भुगतान बेहतर बनाने में कारोबारियों की मदद के लिए सिकोया और टाइगर ग्लोबल जैसे निवेशकों से समर्थित कंपनी ने 'इंस्टैंट रिफंड' नाम से नया उत्पाद पेश किया है।

इस नए फीचर से क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई (यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) जैसे ग्राहकों के स्रोत खाते में रिफंड एक मिनट के भीतर हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया ग्राहकों व दुकानदारों दोनों के लिए दो प्रमुख समस्याओं में से एक है।

बीएस सूडोकू 3640

1				8			5	
2				6		7		
9	8	7	5					
			1				3	9
7	1				9			
					8	4	6	7
		6		4				2
	7			2				1

परिणाम संख्या 3639

8	4	5	1	2	6	9	3	7
6	9	3	8	4	7	2	1	5
1	7	2	3	9	5	6	8	4
5	8	9	7	1	2	3	4	6
4	3	7	5	6	9	1	2	8
2	1	6	4	3	8	7	5	9
7	2	1	6	8	4	5	9	3
9	5	8	2	7	3	4	6	1
3	6	4	9	5	1	8	7	2

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल
★★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2170/2180, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1560/1610, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2170/2180, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3350, चावल (सोना) 2900/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1434, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1510, फ्लैक 1465, डीएमओ 1035, टरपीन लैस बोल्ड 1540

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1200/1250, खुरपा 1100/1125,चाकू 1025/1130, रसकट 940/950, शक्कर 1200/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3370, सिहोरा 3300, बुंदकी 3310, बुढ़ाना 3390,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1030, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4500, खल: सरसों 2200/2300, बिनौला 2500/2600, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2250/2260, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4520/4525,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2140/2150, ग्वार 3800/3850, जौ 2140/2150,

जोधपुर
गेहूं 2150/2200, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7400/7500, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1900/1925, चना 4300/4350, काबली चना 5000/6000, मूंग 6800/6900,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2050, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1325,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7800/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7500/8500, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8700/9400, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5700/5800, शरबती साधारण सेला 3800/3850, शरबती स्टीम 4200/4250,चावल 1509 सेला 4900/4950, धान: शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4140/4170, हरियाणा 4100/4140, राजस्थान 4080/4130, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2550/2650, सरसों खल 2150/2180,

फाजिल्का
गेहूं 2235/2240, सरसों 4500/4525 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4140/4150, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5300/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2650/2700,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2230/2240, चावल परमल कच्चा 2400/2425, से ला 2350/2375, मक्की यूपी 2200/2225, बिहार 2350/2360, दाल उड़द छिलका 9200/10400, चना देशी 5000/5100, दाल चना 5300/5400, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 7800/8200,

करनाल
गेहूं दड़ा 2200/2210, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2950/3000, पूसा 1509 धान 2850/2875, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5175/5200, स्टीम 6050/6150,

हिसार
ग्वार 3800/3850, जौ 1800/1810, सरसों 4150/4175, मूंग 6800/7000, गेहूं 2180/2190,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1090, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 400/500, रिफाइंड (टीन) 1600/1620,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4200/4250, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9200/9250, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1850/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 284

खाद्य तेल का उत्पादन

भारत ने रिफाइंड और प्रसंस्कृत पाम ऑयल के आयात को सीमित किया है। यूरोपीय संघ ने भी परिवहन ईंधन के रूप में पाम ऑयल के इस्तेमाल को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। ये दोनों वैश्विक पाम ऑयल क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाले हो सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल के सबसे बड़े आयातक हैं। दुनिया के कुल उत्पादन में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है। आयात को लेकर भारत के निर्णय पर भले ही मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की जम्मू कश्मीर तथा नए नागरिकता कानून पर टिप्पणियों का असर हो लेकिन इसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसा इसलिए ताकि घरेलू खाद्य तेल उद्योग को बचाया जा सके। यूरोपीय संघ का कदम पाम ऑयल की खेती के पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभावों से प्रेरित है। इसके चलते वन क्षेत्र में कमी आई और तमाम जीवों का रहवास नष्ट हुआ। इसमें दो राय नहीं कि पाम ऑयल की आपूर्ति करने वाले देश विश्व व्यापार संगठन में इसे चुनौती देंगे लेकिन इसका असर शायद ही हो क्योंकि मामला व्यापार से अधिक पर्यावरण से संबंधित है।

भारत के निर्णय पर भी विश्व व्यापार संगठन की शरण ली जाएगी या नहीं यह अभी तय नहीं है। प्रथम दृष्ट्या लगता नहीं कि इससे किसी स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार को क्षति पहुंची हो। न तो यह किसी देश से संबंधित है और न ही आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत केवल रिफाइंड पाम ऑयल के आयात के लिए पूर्व अनुमति को आवश्यक किया गया है। बहरहाल, मलेशिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर अवश्य पड़ेगा। पाम ऑयल मलेशिया का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद है और उसके सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 2.8 फीसदी है। आश्चर्य नहीं कि मलेशिया कीमतों में रियायत के साथ-साथ पाम ऑयल के बदले भारत से चीनी और भैंसे के मांस के आयात में बेहतर सौदेबाजी पर विचार करे। उधर, इंडोनेशिया को कारोबार बढ़ने से लाभ मिलने की आशा है।

भारत की बात करें तो विदेशों से रिफाइंड पाम ऑयल की अबाध आवक रोकने का यह बेहतर अवसर है। मलेशिया नियमित रूप से अपने पाम ऑयल शुल्क ढांचे में बदलाव करता रहता है ताकि रिफाइंड ऑयल के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इससे भारतीय खाद्य तेल उद्योग को नुकसान पहुंचता है। उसने खाद्य तेल की रिफाइनिंग क्षमता में भारी निवेश किया है लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा। औसत क्षमता इस्तेमाल घटकर 46 प्रतिशत रह गया है। कई छोटे और मझोले स्तर की रिफाइनरी बंद हो गई हैं जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सस्ते आयात ने घरेलू खाद्य तेल कीमतों को कम रखा जिसका नुकसान स्थानीय तिलहन किसानों को उठाना पड़ा। घरेलू तिलहन उत्पादन के मांग से तालमेल न बिठा पाने की यह भी एक वजह है।

पाम ऑयल की खेती के मामले में अभी भारत में काफी कुछ किया जाना है। इस दिशा में केवल सरकारी प्रोत्साहन से बात नहीं बनेगी क्योंकि जमीन की उपलब्धता और पौधों को तैयार होने में लगने वाला लंबा वक्त भी बाधा है। भारत में अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने और वृक्ष आधारित तेल की मदद से खाद्य मेल की कमी दूर करने तथा उसे खाद्य प्रसंस्करण, सौंदर्य प्रसाधन और औषधि क्षेत्र में इस्तेमाल करने की पर्याप्त संभावना है। परंतु किसानों द्वारा तिलहन फसलों में निवेश करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जा सके। आयात को कम करके सस्ते खाद्य तेल की आवक को रोकना इस दिशा में एक कदम साबित हो सकता है।

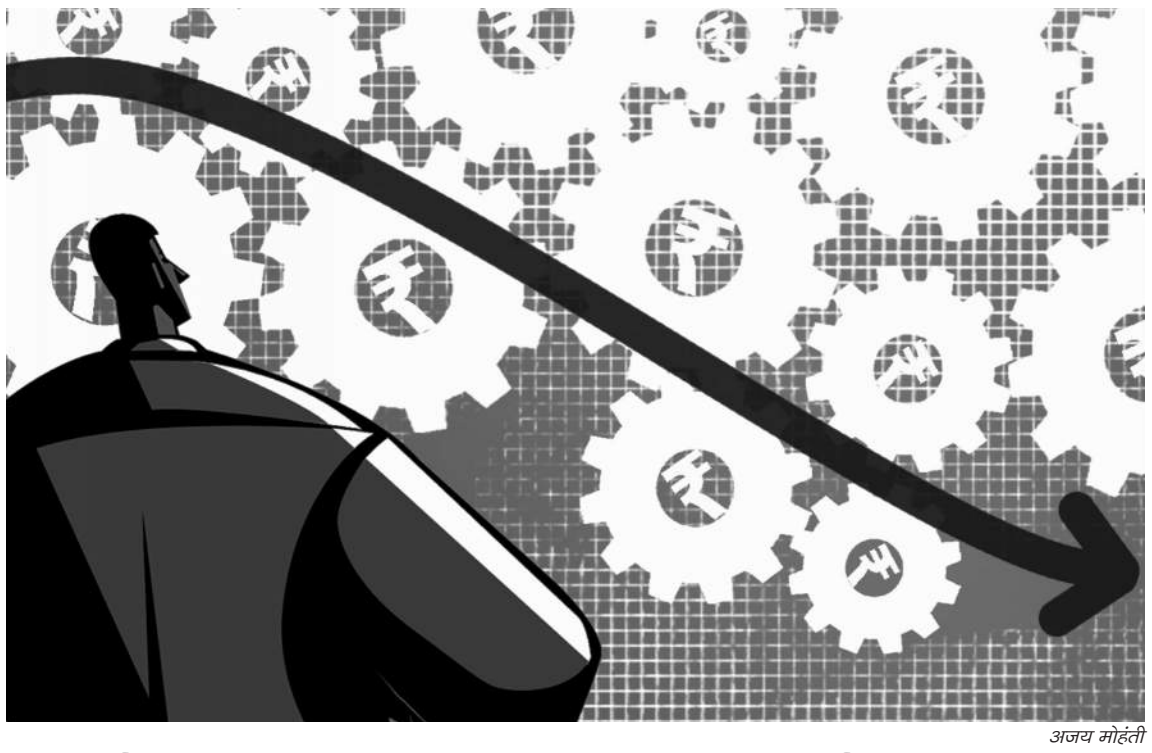

अजय मोहंती

वृद्धि रुझान की फिक्र करें, चक्र की नहीं

नब्बे के दशक से शुरू हुआ उच्च वृद्धि का दौर दो दशक तक चलने के बाद 2011 तक आते-आते शिथिल पड़ गया। इसकी पृष्ठभूमि एवं कारणों की पड़ताल कर रहे हैं **अजय शाह**

वृहद-आर्थिक परिणामों को दीर्घावधि रुझान बनाम अल्पावधि कारोबारी चक्र अनियमितता में बांट देना उपयोगी है। भारत की विकास कहानी में 2011-12 के दौरान वृद्धि रुझान गिरावट पर आ गया था। इससे जुड़ा पहलू यह है कि हमें कारोबारी चक्र परिस्थितियों में पतन देखना पड़ा था। ये दोनों परिघटनाएं आज एक साथ घटित हो रही हैं। भारत में वृहद-आर्थिक नीति के परंपरागत साधन अस्पष्ट हैं और वृद्धि रुझान में गिरावट पर यह ज्यादा फर्क नहीं डाल पाते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र में सबसे अहम सवाल वृद्धि रुझान में गिरावट को समझने और उसे पलटने का है।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकलन से जुड़ी कई समस्याएं हैं। हम मजबूत आंकड़ों से काफी कुछ सीख सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सीएमआईई के आंकड़े करीब 50,000 फर्मों पर निगाह रखते हैं और इससे आधुनिक क्षेत्र के बारे में एक तस्वीर उभरती है। हम अर्थव्यवस्था के सबसे महत्त्वपूर्ण घटक निजी गैर-वित्तीय फर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्ष 1990-91 से लेकर 2011-12 की अवधि में उच्च वृद्धि का दौर रहा था लेकिन उसके बाद वृद्धि दर में नीचे का रुझान है।

बिक्री में वृद्धि के आंकड़ों से हम शुरुआत करते हैं। 1991 से 2011-12 की अवधि में नॉमिनल बिक्री वृद्धि प्रति वर्ष औसतन 16.4 फीसदी रही। उसके बाद के सात वर्षों में यह दर गिरकर 10.5 फीसदी प्रति वर्ष हो गई। निवेश को जांचने का बढ़िया तरीका शुद्ध अचल संपत्तियों की प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 1990-91 से 2011-12 के दौरान इसकी औसत वृद्धि दर 17.4 फीसदी थी और उसके बाद के सात वर्षों में यह अपेक्षाकृत कम 10.3 फीसदी रहा है। यह वृद्धि रुझान में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।

दीर्घावधि वृद्धि रुझान से जुड़ी हुई कारोबार चक्र अनियमितता की परिघटना है। ये कम समय तक चलने वाला उफान और गिरावट है, जो फर्मों के जरिये स्टॉक-निवेश-लाभपरकता की अनिश्चितता का सदाबहार चक्र है। हमारी यहां और अब समस्या 2018 के अंत में शुरू हुए कारोबारी चक्र हालात में पतन है। कारोबार चक्र की उठापटक को कुछ हद तक वृहद-आर्थिक नीति के परंपरागत तरीकों- राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति से भी साधा जा सकता है। हममें से कई लोग समष्टि अर्थशास्त्र की अंतरराष्ट्रीय किताबें पढ़ते रहे हैं और हममें इस निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रवृत्ति होती है कि समष्टिवादी नीति के साधन कारोबार चक्र अनिश्चितता से मुकाबले में कारगर हैं।

हालांकि भारत की स्थिति में हमें अपनी आकांक्षाओं को लेकर बहुत सीमित होना चाहिए। भारत में राजकोषीय नीति इस तरह से नहीं बनी है जो स्थिरीकरण में मदद करे। वर्ष 2015 में मुद्रास्फीति को काबू में रखने की शुरुआत होने से पहली बार मौद्रिक नीति कारोबार चक्र स्थिरीकरण में मदद मिलने लगी है। जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को चार फीसदी के नीचे रखना चाहती है तो इससे कारोबारी चक्र उठापटक पर काबू पाने के लिए नीतिगत दरों में कभी तेजी तो कभी नरमी के हालात बनेंगे। उसी के साथ हमारे पास एक अल्पविकसित वित्तीय प्रणाली होने से आरबीआई की क्षमता भी सीमित है।

हमें मुद्रास्फीति नियंत्रण का काम ठीक से करना चाहिए लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत में इसकी क्षमता कम है और हमें पता होना चाहिए कि भारत में राजकोषीय नीति समष्टि-अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण का हिस्सा नहीं है। नतीजतन, किताबों की तरह भारत में वृहद आर्थिक नीति के जरिये स्थिरीकरण नहीं हो पाता है। वैसे हमें बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। कारोबार चक्र की हरेक गिरावट के बारे में एक बात अच्छी है कि अगर उसे यूं ही छोड़ दें तो वह खुद-ब-खुद ठीक हो जाएगी। भारत में कारोबारी उठापटक का लंबा इतिहास हमें आश्वस्त करता है कि वृहद नीतियों के निष्प्रभावी एवं भ्रमित होने के बावजूद अतीत में गिरावट थम गई।

इससे कहीं बड़ी समस्या वृद्धि रुझान में गिरावट है जिस पर हमें फिक्र करनी चाहिए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अहम सवाल यह है कि 1990 से 2011 के दौरान हमारी वृद्धि इतनी ऊंची क्यों थी और फिर 2011 के बाद इसमें गिरावट का रुझ क्यों रहा? इस समस्या को समझ पाने में हम जिस हद तक कामयाब होते हैं और ठोस बौद्धिक समझ के आधार पर अपने रास्ते बदल पाते हैं तो वह कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होगा।

इस प्रक्रिया में हमें कारण और प्रभाव की सरलीकृत धारणाओं से परहेज करना चाहिए। इस बात का खतरा है कि 1991 में शुरू हुए उच्च वृद्धि के सिलसिले के लिए जुलाई 1991 के बजट भाषण को श्रेय दिया जाए। इसी तरह इस उफान के खत्म होने के लिए प्रणव मुखर्जी के 2011 के बजट भाषण को जिम्मेदार मानने का भी खतरा है। लेकिन इस पैमाने की सामाजिक परिघटना साधारण व्याख्या से रोकती है। वृद्धि रुझान में बदलाव ऐतिहासिक कारणों और कई वर्षों की मानव गतिविधियों का सामूहिक नतीजा रहा है।

1991-2011 बूम की बुनियाद कई कारकों ने रखी थी। भारतीय समाजवाद से दूर जाती आर्थिक नीति का भी इसमें योगदान रहा है। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से 1991 तक कई कदम उठाए गए। जुलाई 1991 में बजट भाषण इस दिशा में नाटकीय बदलाव लाने वाला साबित हुआ।

इसी अंदाज में इस वृद्धि प्रकरण का अंत 2011-12 में मानव कृत्यों से नहीं हुआ था। जब भारत की जीडीपी काफी बढ़ गई तो हमारे संस्थान बड़ी एवं अधिक जटिल अर्थव्यवस्था से निपटने में नाकाफी रहे थे। एक परिष्कृत निजी अर्थव्यवस्था को आपराधिक न्याय व्यवस्था, विवाद निपटान, न्यायपालिका, आर्थिक नियमन और कर प्रणाली में काबिलियत की जरूरत होती है। इसके लिए आर्थिक आजादी एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के इर्दगिर्द बुनी लोक नीति के मूल्यों की जरूरत होती है। लेकिन हम वर्ष 2014 में दो लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी पर सिमटकर रह गए जिसकी संस्थागत क्षमता 1982 की 20 हजार करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था लायक ही थीं।

समय बीतने के साथ निजी क्षेत्र की जरूरतों एवं संस्थाओं की क्षमताओं के बीच असंतुलन लगातार बिगड़ता गया। इस बढ़ते असंतुलन ने 2011-12 में वृद्धि प्रकरण का अंत कर दिया।

इस वृद्धि प्रकरण के माध्यम से निजी कारोबारियों की नजर में उम्मीद एवं अनुभव के बीच तनाव देखा गया। उस दौरान संस्थानों के कामकाज में कई कमजोरियां थीं। हालांकि निजी स्तर पर लोग अपने अविश्वास को तिलांजलि देने को तैयार थे और वे यह मानना चाहते थे कि आज हालात खराब होने के बावजूद वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से समय-समय पर विपदा खड़ी करने पर समाधान निकाल लिया जाएगा। भारत के प्रति प्रतिबद्ध होने, भारत में ही कारोबार खड़ा करने और भारत में वित्तीय पूंजी निवेश करने के साथ यह मान्यता भी थी। वर्ष 2011-12 तक बदल जाने वाली बात यह थी कि इस आशावाद का क्षय हो गया।

चार दिन का कामकाजी हफ्ता अभी महज आकांक्षा ही रहेगा

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

फिनलैंड की युवा प्रधानमंत्री सना मारिन ने चार कार्य दिवस के सप्ताह को अपना समर्थन देकर दुनिया भर के कर्मचारियों का दिल जीत लिया है। इस घोषणा से कर्मचारियों को होने वाले लाभ पूरी तरह स्पष्ट हैं: बिना कामकाजी दायित्व का एक और दिन मिलने के साथ ही उन्हें सफर भी नहीं करना पड़ेगा। इससे उनके पास अधिक व्यक्तिगत समय होगा जिससे उनके तनाव में कमी और उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

कुछ वैश्विक कंपनियां पहले ही चार दिन का सप्ताह लागू कर बढ़िया नतीजे हासिल कर चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जापान में इसे गत अगस्त में लागू किया था और इस दौरान अपनी बिक्री में 40 फीसदी वृद्धि होने का दावा किया। इस प्रयोग के अन्य लाभ भी हैं। कंपनी का बिजली उपभोग एक चौथाई तक गिर गया और मुद्रित किए गए कागजों में भी 59 फीसदी गिरावट आई। दूसरी कंपनियों ने भी चार दिन के कामकाजी सप्ताह की दिशा में प्रायोगिक परीक्षण किए हैं और उन्हें भी ऐसे ही नतीजे मिले हैं। हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू में एक और परीक्षण के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट भी बताती है कि छोटे कामकाजी सप्ताह में उत्पादकता बढ़ गई।

इन परिणामों से अचरज नहीं होना चाहिए क्योंकि खुशहाल कर्मचारी कंपनी की समग्र समृद्धि में योगदान देते हैं। असल में, समूचे इतिहास में यह देखा गया है कि कामकाजी घंटे कम होने पर उत्पादकता बढ़ी है। हेनरी फोर्ड ने 1926 में जब पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू किया तो उन्हें भी ऐसे नतीजे मिले थे। फोर्ड 40 घंटे का कार्य सप्ताह लागू करने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक है। उसके चार साल बाद केलॉग ने जब एक दिन में छह घंटे की ड्यूटी लागू की तो कारखाने में होने वाले हादसे 40 फीसदी तक कम हो गए।

सवाल उठता है कि क्या कंपनियों को चार दिवसीय कार्य सप्ताह के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने का वक्त आ गया है? दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इसका जवाब ना है। यहां तक कि फिनलैंड भी ऐसा कुछ करने की नहीं सोच रहा है। मारिन की घोषणा के बाद जिस तरह से धन्यवाद देने वाले संदेशों की भरमार हुई तो उनके कार्यालय को यह सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा कि चार दिन का हफ्ता सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है और निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना भी नहीं है। लोगों की निराशा उस समय और बढ़ गई जब यह पता चला कि मारिन ने यह बयान प्रधानमंत्री बनने के पहले दिया था और यह महज आकांक्षा-जनित बयान था।

हफ्ते में चार दिन काम कर पूरा वेतन लेने वाले कर्मचारियों का विचार व्यवहार्य नहीं होने के पीछे एक वजह है। कार्यदिवसों में कोई भी कटौती तब तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है जब तक उत्पादकता में आनुपातिक वृद्धि या वेतन में समान कटौती न की जाए। यह सच है कि कर्मचारियों को बढ़ी उत्पादकता और मनोबल के संदर्भ में कुछ लाभ मिलेंगे लेकिन चार दिन के कामकाजी हफ्ते से मुनाफा बढ़ने की संभावना होने पर ही कोई कंपनी इसे लागू करेगी।

एक और समस्या यह है कि चार-दिवसीय कार्य सप्ताह को सेवा क्षेत्र में लागू करना मुश्किल हो सकता है जहां ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी समर्थित एक अध्ययन ने थकावट बढ़ने को लेकर आगाह भी किया क्योंकि अनुबंधित कर्मचारियों पर इन चार दिन में काम का बोझ रहेगा। इसके अलावा अकुशल एवं अस्थायी कामगारों पर इसका नकारात्मक असर भी पड़ेगा क्योंकि उन्हें घंटों के हिसाब से भुगतान होता है।

इसकी वजह यह है कि नियोक्ताओं का काम हफ्ते के पांचों दिन आठ घंटे प्रतिदिन के पूर्णकालिक कार्य-सप्ताह से कम पर नहीं चल सकता है। अगर वे चार दिवसीय सप्ताह अपनाते हैं तो कर्मचारियों को रोजाना 10-10 घंटे काम करना होगा। ऐसे में लोग हफ्ते में एक और दिन का अवकाश मिलने से खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं लेकिन एक दिन में काम पर लंबा वक्त बिताने से उनकी उत्पादकता कम भी हो सकती है।

अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र की बड़ी मानव संसाधन फर्म ट्रीहाउस ने वर्ष 2016 में चार-दिवसीय सप्ताह लागू किया था लेकिन प्रतिस्पर्द्धा में टिक पाना मुश्किल होने पर वह फिर से पांच-दिवसीय सप्ताह की तरफ लौट आई। ट्रीहाउस के मुख्य कार्यकारी रेयान कार्सन ने दी वाशिंगटन पोस्ट से कहा था, 'अगर आप अपने प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में 80 फीसदी वक्त ही काम कर रहे हैं तो मुकाबला कर पाना खासा मुश्किल हो जाता है।'

मोटे तौर पर यह साफ है कि एक सप्ताह में कुल कामकाजी घंटों को नीचे लाने की जरूरत है। शोध से पता चला है कि हफ्ते में 50 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी के योगदान में गिरावट आती है और 55 घंटे के बाद तो यह धराशायी ही हो जाता है। शोध बताते हैं कि जो कर्मचारी हफ्ते में 70 घंटे तक काम करते हैं वे असल में अतिरिक्त 15 घंटों में कोई उत्पादक काम नहीं करते हैं। यह साक्ष्य है कि दफ्तर में देर रात तक समय बिताने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि योगदान बढ़ा ही है और इससे समझदार कर्मचारी भी हाशिये पर धकेले जा सकते हैं।

खतरा यह है कि मुख्य कार्याधिकारी के आसपास ऐसे मल्टी-टास्किंग, तीव्रगामी 'जॉम्बी' इकट्ठा हो जाएंगे जो यह सोचे बगैर हमेशा लिफ्ट का बटन दबाते रहते हैं कि इससे लिफ्ट काम करना बंद कर देगी।

लेकिन भारतीय कंपनी जगत चार दिवसीय कार्य सप्ताह इसलिए नहीं लागू कर सकता है कि यह काफी महंगा है। इस तरह की सोच पर अमल करने का सीधा मतलब है कि आपको नए कर्मचारी रखने होंगे और ऐसा कर पाना उनके लिए आर्थिक रूप से सही नहीं होगा। इस तरह मौजूदा समय में यही बेहतर है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को कामकाज के लचीले घंटे और घर से काम करने की छूट दें और चार दिन के हफ्ते को फिलहाल आकांक्षा ही रहने दें।

कानाफूसी

छोटे दलों की भरमार

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में माना जा रहा है कि वहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। कुछ लोग कांग्रेस को भी इस लड़ाई में शामिल मान रहे हैं। इस बीच इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे छोटे दलों की भी कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कहा है कि वह सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसने 15 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। इतना ही नहीं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल समेत बिहार के कुछ अन्य राजनीतिक दलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में मजबूत मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी भी यहां चुनाव मैदान में उतर सकती है। हरियाणा में भाजपा की साझेदार जननायक जनता पार्टी भी सीमावर्ती इलाकों में अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है।

जातीय समीकरण

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। खासतौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा में पार्टी के नेता दानिश अली को हटाकर उनकी जगह रीतेश पांडेय को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया है। जाहिर है उनकी कोशिश ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने की है। दिलचस्प बात है कि आठ महीनों में चौथी बार मायावती ने ऐसा बदलाव किया है। मायावती का कहना है कि हालिया बदलाव जातीय संतुलन कायम करने के लिए किया गया है क्योंकि एक अन्य मुस्लिम नेता पहले से पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। हालांकि उनके आलोचकों की दलील है कि ऐसे तो एक अन्य ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं।

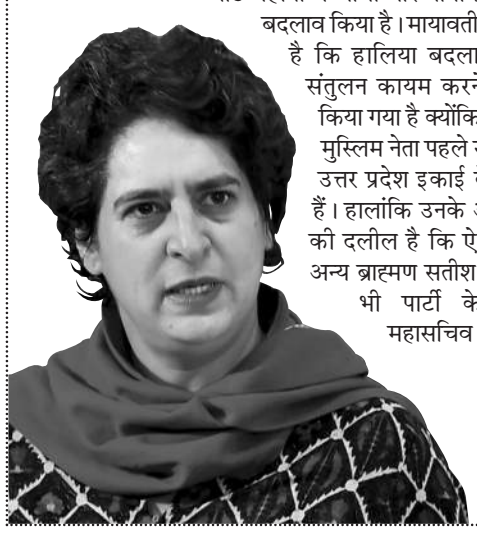

आपका पक्ष

न्याय प्रक्रिया में तेजी लानी होगी

हाल में आई एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से 17.6 प्रतिशत (69,861) अधिक है। अगर राज्यवार जेलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 76.5 प्रतिशत और सिक्किम में 57.3 प्रतिशत क्षमता से अधिक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर, 2018 तक कुल कैदियों की संख्या 4,66,084 थी जिनमें से 30 प्रतिशत (1,39,488) दोषी करार दिए गए हैं, जबकि 69 प्रतिशत (3,23,537) कैदी विचाराधीन हैं। ये आंकड़े हमारी न्यायिक प्रक्रिया के साथ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं। इसके लिए पुलिस की कार्यप्रणाली से लेकर न्यायाधीशों की कमी जैसे सभी महत्त्वपूर्ण कारण हैं। समय-समय पर मानवाधिकार आयोग और शीर्ष न्यायालय भी जेलों में कैदियों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के साथ राज्य सरकारों को चाहिए कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी और मूलभूत अवसंरचना की कमी को दूर करे और पुलिस को भी निष्पक्ष होकर अपने कार्यों को उचित समय में प्रभावी ढंग से करना चाहिए जिससे विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम किया जा सके। इसके अलावा सरकार को जेलों की संख्या बढ़ाने, अन्य जेलों में क्षमता से अधिक रह रहे कैदियों को नई बनी जेलों में स्थानांतरित करने की जरूरत है।

सरकार को न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए

सचिन यादव, अंबेडकर नगर

अर्थव्यवस्था में सुधार के कदम

भारत को आर्थिक मंदी दूर करने के उपाय करने चाहिए। कल कारखाने लगाकर बेरोजगारी दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए। देश में शिक्षा के स्तर में सुधार की जरूरत है तभी देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। देश में सार्वजनिक परिवहन के साथ माल ढुलाई की व्यवस्था में सुधार की भी जरूरत है। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की भी जरूरत है क्योंकि इससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत है क्योंकि जीडीपी दर कम हो गई है। मनोरंजन के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। इन सभी सुधारों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकेगी।

राकेश जैन, सतना

एनआरसी से बढ़ेगा अर्थव्यवस्था पर बोझ

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून के लगातार हो रहे विरोध के बीच डिटेंशन सेंटर का नाम उभर कर सामने आया है। डिटेंशन सेंटर वह स्थान है जहां अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को रखा जाता है। केंद्र सरकार के लिए एक चिंतनीय मुद्दा यह भी है कि अगर पूरे भारत में एनआरसी लागू किया जाता है तो क्या जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को डिटेंशन सेंटर में रखने की व्यवस्था हो पाएगी। अगर सरकार एनआरसी लागू करने की योजना बना रही है तो अनेक समस्याओं का समाधान खोजना होगा। एक तरफ एक बड़ी आबादी को रखने की समस्या है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी है। ऐसे में देशभर में एनआरसी कराने पर अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा जो उचित नहीं है।

अनु मिश्रा, सीवान

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

किसानों ने पकड़ी ऑनलाइन की राह

स्टार एग्री और एनसीएमएल ग्राहकों और एफपीसी को ऑनलाइन उत्पाद बेचने की कर रहीं पेशकश, दलालों की छुट्टी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 15 जनवरी

- **औरंगाबाद के सुल्तानपुर की सबसे बड़ी एफपीसी में से एक स्वरूप सत्कारी एफपीसी पर इस इलाके के करीब 400 किसान पंजीकृत हैं**
- **किसानों को मक्का, सोयाबीन, दलहन और अन्य कृषि जिंसों को सीधे थोक विक्रेताओं और कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं को बेचने की है सुवि**
- **मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंग आंध्र प्रदेश, पंजाब में भी बिचौलियों की छुट्टी क कारोबार का उठा**

सुल्तानपुर (औरंगाबाद) के किसान दीपक चौहान के पास छह एकड़ जमीन है। वह अपनी 20 फीसदी अतिरिक्त कमाई से एक एकड़ और जमीन लेने की योजना बना रहे हैं। यह कमाई उन्होंने अपने उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से सीधे कॉर्पोरेट खरीदारों को बेचकर की है। यह काम वह स्वरूप सत्कारी एफपीसी लिमिटेड नामक अपनी किसान उत्पाद कंपनी (एफपीसी) के माध्यम से कर रहे हैं। सुल्तानपुर की सबसे बड़ी एफपीसी में से एक स्वरूप सत्कारी एफपीसी पर इस इलाके के करीब 400 किसान पंजीकृत हैं। यहां किसानों को मक्का, सोयाबीन, दलहन और अन्य कृषि जिंसों को सीधे थोक विक्रेताओं और कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं को बेचने की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वरूप सत्कारी एफपीसी की तरह पूरे महाराष्ट्र में 300 से अधिक एफपीसी पंजीकृत हैं जहां (छोटे, मझोले और बड़े) किसानों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने की सुविधा मुहैया कराई जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि बड़े कृषि राज्यों में भी एफपीसी बिचौलियों की छुट्टी कर ऑनलाइन कारोबार का लाभ उठा रही हैं और अपने उत्पाद का उच्च मूल्य हासिल कर रही हैं।

वायदा बाजार का लाभ उठाने के लिए कई एफपीसी ने नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) की सदस्यता ली है। यहां से वे वायदा कीमत की जानकारी लेकर उत्पाद बेचने का निर्णय लेती हैं जिससे उन्हें अच्छी कीमत हासिल होती है। एनसीडीईएक्स किसानों को वायदा बाजार की समझदारी पूर्वक इस्तेमाल में मदद करता है ताकि वे अपने उत्पाद पर अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें। चौहान ने कहा, 'हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर वायदा और हाजिर बोलियों के जरिये सफलतापूर्वक मक्के और सोयाबीन की बिक्री की है। पहले हमें ऋणदाताओं को तुरंत भुगतान करने के लिए अपनी उपज को आनन-फानन में बेचना पड़ता था। लेकिन हमारी एफपीसी ने हमें अच्छी कीमत हासिल करने में मदद की है। केवल इस वर्ष ही हमने सफलतापूर्वक ऑनलाइन बिक्री कर 20 फीसदी अधिक लाभ कमाया है।'

चौहान जैसे कई किसानों ने इस विकल्प को अपनाया है और मजबूरी में बिक्री करने से बच रहे हैं। एफपीसी और दूसरे ऑनलाइन साझेदार ऋणदाताओं का बकाया चुकाने के लिए किसानों को रकम जुटाने और अपने उत्पाद ऊंची कीमत पर बेचने में मदद करते हैं।

इसके अलावा स्टार एग्रीवेयरहाउसिंग ऐंड कोलेटेरल मैनेजमेंट लिमिटेड (स्टार एग्री) और नैशनल कोलेटेरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएल) ने भी अपने ग्राहकों को ऊंची कीमतें दिलाने के लिए अपना ऑनलाइन जिंस कारोबार प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पर ग्राहकों की कृषि जिंसों की बोली लगाई जाएगी।

स्टार एग्री ने एग्रीबाजार डॉट कॉम और एनसीएमएल ने मार्केटयार्ड डॉट कॉम नाम से अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिस पर ग्राहकों को उत्पाद बेचने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। एक अन्य गोदाम कंपनी नैशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन (एनबीएचसी) ऑनलाइन कारोब प्लेटफॉर्म लाने पर विचार कर रही है पर वह अपने ग्राहकों को कृषि उ थोक उपभोक्ताओं को बेचने की सुविधा देगी। इस प्रकार इस कंपनी के ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दलालों की जरूरत नहीं होगी, लिहाजा उन्हें अच्छी कमाई होगी। स्टार एग्री के सह संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी अमित अग्रव ने कहा, 'एग्रीबाजार पर हमने 1. डॉलर मूल्य का लेनदेन किया है लाख टन से अधिक कृषि उ की है जिसमें मोटे तौर मसाले, सेब और फिलहाल, हमा के लिए 1,5 जुड़े हुए ओर में सेवाओं के अपने म के लि

वाणिज्यिक खन की नीलामी

भाषा
नई दिल्ली, 15 जनवरी

सरकार ने आ में वाणिज्यि खनन के नील

आवक बढ़ने से सब्जियों में नरमी

दिसंबर में तेज इजाफे के बाद जनवरी में आवक बढ़ने से ठंडे पड़ने लगे सब्जियों के दाम

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 15 जनवरी

सब्जियों के दाम दिसंबर में तेजी से बढ़ने के बाद जनवरी में इनमें नरमी आई है। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत प्रमुख उत्पादक राज्यों में आवक बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। जिंसों के खुदरा दामों का अनुसरण करने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की घोषणा करते हुए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने दिसंबर के दौरान हरी सब्जियों के दामों में 60 प्रतिशत इजाफे की जानकारी दी थी। हालांकि जनवरी में हरी सब्जियों के खुदरा दामों में तेज गिरावट आई है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े बताते हैं कि भिंडी के खुदरा दामों में 33 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और मुंबई में इसके दाम फिलहाल 40 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रहे हैं। इसी तरह कोलकाता के खुदरा बाजार में अब गोभी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बिक रही है, जबकि जनवरी की शुरुआत में इसके दाम 26 रुपये प्रति किलोग्राम थे। इसके दामों में 42 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी ओर, रिकॉर्ड ठंड वाले मौसम की वजह से आपूर्ति की चिंता और बड़े स्तर पर बरबादी के कारण दिल्ली के बाजारों में थोक और खुदरा बिक्री में सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हुआ है।

हरी सब्जियों के दामों में अक्टूबर से तेजी आने लगी थी, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ से खरीफ फसल की बरबादी और खेती वाले राज्यों में बेमौसम बारिश के कारण रबी फसल की बुआई में देरी की खबरों से दिसंबर में दाम करीब दोगुने हो गए थे।

नाशिक की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के सचिव अरुण काले ने कहा कि मॉनसून सीजन में बाढ़ की वजह से पूरे महाराष्ट्र में खरीफ फसल को भारी नुकसान हुआ था। मॉनसून सीजन के बाद बीच-बीच में होने वाली बारिश से मिट्टी में नमी की अधिकता के कारण रबी सब्जी की बुआई में चार सप्ताह की देरी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप रबी सब्जी की कटाई में भी इसी अनुपात में देरी हुई। चूंकि पिछले दो सप्ताह के दौरान बड़ी मात्रा में आपूर्ति शुरू हो चुकी है, इसलिए सब्जियों के दामों में नरमी आ गई है। आगे आवक में लगातार इजाफा होने से सब्जियों के दामों में नरमी जारी रहेगी। जनवरी के पहले दो सप्ताह के दौरान अधिकांश सब्जियों की नए सीजन की आवक में 50 से 100 प्रतिशत तक की उछाल आई है।

दामों में तीव्र वृद्धि ने इस साल देश भर के कई किसानों को सब्जियों के अंतर्गत रकबा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता की वजह से पिछले वर्षों की अपेक्षा इस सीजन के दौरान किसानों को बेहतर उपज दिलाने में मदद मिली है। धूप वाले दिनों और सर्द रातों के साथ कृषि के अनुकूल मौसम से पौधों के अंकुरण, पुष्पण और फल के विकास में मदद मिली है। वेजिटेबल्स ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीराम गाढवे ने कहा कि आने वाले सप्ताहों में सब्जियों के दामों में कमी आएगी क्योंकि मंडियों में रबी सीजन की आवक आनी शुरू हो गई है।

जनवरी में अन्य सब्जियों के अलावा प्याज के खुदरा दामों में भी तेज गिरावट देखी गई है। दिल्ली में प्याज के खुदरा दाम 35 प्रतिशत गिरकर फिलहाल 65 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रहे हैं, जबकि दो सप्ताह पहले दाम 100 रुपये प्रति किलोग्राम थे।

सांगली के वसंतदादा मार्केट यार्ड के चेयरमैन एसएस पाटिल ने कहा कि हालांकि इस साल सब्जियों के खुदरा दामों में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन किसानों को इस दाम वृद्धि का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया है। सब्जियों के दामों में इस इजाफे का ज्यादातर फायदा व्यापारियों और आढ़तियों को मिला है। वे किसानों से कम दामों पर सब्जियों की खरीद करते हैं और कई गुना लाभ के साथ मंडियों या बड़े उपभोक्ताओं को अधिक दामों पर बेचते हैं।

फोटो-पीटीआई

सस्ती होने लगी सब्जी

- हरी सब्जियों के दामों में अक्टूबर से आने लगी थी तेजी
- महाराष्ट्र में खरीफ फसल बरबाद होने की खबरों और रबी फसल की बुआई में देरी के कारण दिसंबर में करीब दोगुने हो गए थे दाम
- सीएसओ ने दिसंबर के दौरान हरी सब्जियों के दामों में 60 प्रतिशत इजाफे की जानकारी दी थी
- एनएचबी के आंकड़े के अनुसार भिंडी के खुदरा दामों में 33 प्रतिशत तक की गिरावट आई

इस्पात उत्पादकों ने बजट में सरकार से की मांग

पेट कोक, कोकिंग कोल को शुल्क मुक्त किया जाए

जयजित दास
भुवनेश्वर, 15 जनवरी

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारी के बीच इस्पात उत्पादकों ने पेट कोक, कोकिंग कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला और मेटलर्जिकल कोयले पर आयात शुल्क में भारी कटौती करने की मांग की है। घरेलू संसाधनों की कमी के चलते देश के इस्पात निर्माता इन कच्चे माल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

मौजूदा शुल्क संरचना के तहत कोकिंग कोल तथा एंथ्रेसाइट कोयला, दोनों पर 2.5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। साथ ही, भारत सरकार पेट कोक के आयात पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाती है।

एक प्रमुख स्टील उत्पादक कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'एंथ्रेसाइट कोयला, कोकिंग कोयला तथा पेट कोक स्टील बनाने के लिए अहम होते हैं। इन आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती से लागत प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में मदद करेगी। मात्रा एवं गुणवत्ता, दोनों मामलों में इनकी अनुपलब्धता घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बाधित कर रही है।' देश में उपयोग होने वाले कम राख वाले मेटलर्जिकल कोयले का 50-80 प्रतिशत आयात होता है।

बजट के लिए दिए गए अपने प्रस्ताव में फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (फिमी) ने सुझाव दिया है कि कम राख वाले मेटलर्किल कोयले पर आयात शुल्क वर्तमान के 10 प्रतिशत से कम करके 2.5 प्रतिशत किया जाए, जिससे घरेलू उद्योग को लाभ मिल सके और आयात से घरेलू उत्पादकों को नुकसान न पहुंचे।

फिमी का कहना है, 'पेट कोक (दो प्रतिशत सल्फर ग्रेड) कोक का अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प है और इसलिए इसे घरेलू उद्योग में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन की लागत कम करके घरेलू स्टील मिलों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।'

कोकिंग कोल पर आयात शुल्क समाप्त करने का समर्थन करते हुए फिमी ने तर्क दिया कि पहले भी कोकिंग कोयले पर कोई आयात शुल्क नहीं था और बजट 2014-15 में सरकार ने इस पर शुल्क लगाते हुए दूसरे प्रकार के कोयलों के समान ला दिया था।

फिमी ने कहा, 'इस संशोधन से मेक इन इंडिया तथा भारतीय स्टील निर्माताओं पर नकारात्मक असर हुआ। कोकिंग कोयला स्टील बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल का अहम हिस्सा है। कोकिंग कोल पर 2.5 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ-साथ पांच प्रतिशत आयात शुल्क लगाने से स्टील की लागत पर प्रतिकूल असर पड़ा है।'

- कोकिंग कोल तथा एंथ्रेसाइट कोयले पर 2.5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है
- सरकार पेट कोक के आयात पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाती है
- देश में उपयोग होने वाले कम राख वाले मेटलर्जिकल कोयले का 50 से 80 प्रतिशत आयात होता है

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 15	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,767.5	3.8	2,047.4	7.7
Copper	6,247.0	8.7	6,594.2	10.2
Nickel	13,680.0	-19.9	14,685.1	-17.9
Lead	1,897.0	-11.5	2,216.9	5.0
Tin	17,320.0	5.0	18,356.4	5.9
Zinc	2,364.0	-3.0	2,612.3	-1.1
Gold ($/ounce)	1,551.9*	4.8	1,741.6	4.1
Silver ($/ounce)	17.8*	2.4	20.2	1.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	64.9*	11.1	65.3	9.4
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-7.7	2.2	-8.0
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	197.3	15.5	319.7	10.5
Maize	194.0*	7.2	336.6	14.7
Sugar	390.9*	12.5	493.6	0.7
Palm oil	777.5	49.5	1,260.2	48.3
Rubber	1,591.3*	15.0	1,927.4	14.9
Coffee Robusta	1,291.0*	4.4	1,934.5	-7.7
Cotton	1,553.4	10.9	1,643.8	2.4

* As on Jan 15, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.8& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	85.1	31674
Oil and Oilseeds	393.1	71799
Spices	0.1	9
Metal(Jan 14)		
Metal- non ferrous	5228.3	50105
Metal- precious	10503.4	426
Oil and gas(Jan 14)		
Gas	2872.0	48439
Oil	14028.1	1943

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	140.0	127919
Grains	124.7	100895
Oil and Oilseeds	810.4	515005
Others	81.5	66755
Pulses	41.5	28940
Spices	50.0	25787

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	158.8	3.2
Cardamom (Feb 14)	3820.0	0.9
Lead Mini (Jan 31)	152.3	0.9
Copper (Jan 31)	453.9	0.7
Zinc (May 29)	184.7	0.3
Crude Oil (Jan 17)	4138.0	0.1
Losers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Jan 31)	805.3	-1.9
Silver Micro (Feb 28)	45929.0	-1.2
Silver Mini (Feb 28)	45929.0	-1.2
Silver (Mar 05)	45903.0	-1.2
Nickel (Jan 31)	1018.3	-1.1
Mentha Oil (Jan 31)	1274.2	-0.7

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6436.0	1.2
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4126.0	0.5
Chana-Bikaner (Jan 20)	4470.0	0.4
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4367.0	0.3
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6412.0	0.1
Losers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2069.0	-1.2
Jeera Unjha (Jan 20)	15595.0	-1.0
Soyabean Indore (Jan 20)	4236.0	-0.9
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1126.5	-0.8
Guar Seed 10 (Jan 20)	4096.0	-0.7
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	919.8	-0.6
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7324.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19790.0	1.1
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3820.0	0.7
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1274.2	-9.6
Alumini-Mumbai (Jan 31)	140.4	-2.3
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	182.2	-1.9
Lead Min Mumbai (Jan 31)	152.3	-1.8
Lead Mum (May 29)	152.9	-1.4
Gold Petal-Mumbai (Jan 31)	3940.0	-1.0
Nickel Mumbai (Jan 31)	1018.3	-0.9
Copper Mum (Jan 31)	453.9	-0.8
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	-0.6
Silver Ahm (Mar 05)	45903.0	-0.6

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6412.0	3.8
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	839.1	1.8
Moong-Merta City (Jan 20)	7908.0	1.4
Maize-Sangli (Jan 20)	2054.0	0.3
29 mm Cotton-Rajkot (Jan 20)	19600.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6436.0	-6.6
Soy Bean Indore (Jan 20)	4236.0	-3.0
Jeera Unjha (Jan 20)	15595.0	-2.9
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3153.0	-1.5
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7324.0	-1.2
Bajra-Jaipur (Jan 20)	1971.0	-0.4

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals		Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	109	(109)
Aluminium ingots /kg	145	(145)
Brass sheet cutting /kg	325	(320)
Brass utensil scraps/kg	312	(306)
Copper heavy scrap /kg	435	(435)
Copper utensil scraps/kg	405	(407)
Copper wire bar /kg	467	(468)
Lead ingots /kg	157	(157)
Nickel Cathodes /kg	1040	(1040)
Tin slabs /kg	1300	(1290)
Zinc slabs /kg	185	(185)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton		Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10264	(10264)
DCH - 32 /Qtl	11585	(11585)
Jaydhar /Qtl	9983	(9983)
Shankar- 6 /Qtl	11389	(11389)

Source:Cotton Association of India

Oil		Mumbai
Castor FSG /10kg	878	(878)
Castor Comm /10kg	868	(868)
Groundnut oil /10kg	1150	(1160)
Palm oil /10kg	885	(892)
Sunflower exp ref /10kg	930	(930)
Sunflower oil exp /10kg	900	(900)
Soyabean ref / 10kg	920	(925)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar		Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3412-3580	(3400-3592)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel		
NYSE Crude	58.11	(58.23)
Brent Crude (UK)	64.87	(64.88)
Brent Crude (WTI)	58.23	(58.23)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.15	(2.19)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	317.45	(321.62)
Naptha spot /Rs/MT	45170	(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150	(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950	(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold		Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39654	(39475)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	39813	(39634)
Silver.999/ kg	45960	(45835)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19581.10	19569.60
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.00	143.70
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2055.00	1970.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1990.45	1979.40
Barley Jaipur (N)	1 Q	2200.00	2198.65
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3833.00	3833.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4221.60	4205.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4210.00	4210.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4350.00	4377.50
Chana Delhi (N)	1 Q	4568.10	4593.65
Chana-Akola (N)	X	4384.40	4384.40
Coriander-Gondal (N)	X	6625.00	6600.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6900.00	6900.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6894.35	6894.35
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2139.80	2111.40
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2125.00	2087.20
Cotton-Kadi (N)	1 B	19600.65	19600.65
CPO-Kandla (M)	10 K	826.80	826.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	836.90	824.05
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	825.00	825.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	902.85	902.25
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1544.75	1542.55
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3440.60	3433.75
Gold Ahm (M)	10 G	39602.00	39602.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31809.00	31809.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3962.00	3979.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7387.50	7416.40
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4050.00	4068.90
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4025.00	4050.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1148.85	1131.95
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	100.00	100.75
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16800.00	16400.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16100.00	16061.75
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	920.70	905.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1073.65	1073.65
Kapas-Rajkot (N)	X	1074.80	1072.55
Lead Mum (M)	1 K	155.15	155.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1969.40	1969.40
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2391.35	2391.35
Maize-Erode (N)	X	2045.00	2045.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2255.00	2230.00
Maize-Sangli (N)	X	2051.65	2048.45
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	5000.00	5000.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7900.00	7800.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4540.00	4488.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	1026.10	1027.50
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3150.00	3200.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3159.00	3207.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	344.50	343.60
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34633.35	34500.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	905.00	893.75
Rape mustards-Patan (I)	20 K	812.00	815.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1977.50	1953.35
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5260.00	5189.75
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	892.50	892.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	930.00	921.15
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	928.70	927.65
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	942.50	942.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13600.00	13650.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13600.00	13700.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46189.00	46189.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4362.00	4366.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4292.50	4292.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4416.25	4416.25
Soy Bean-Akola (N)	X	4293.00	4293.00
Soymeal Indore (N)	1 T	35100.00	35250.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	931.20	922.20
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32420.00	32400.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32360.00	32520.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29490.00	29630.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3305.00	3300.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3405.65	3428.55
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3320.55	3307.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3495.25	3495.25
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3340.65	3341.35
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3166.65	3169.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6179.75	6179.75
Wheat Delhi (N)	1 Q	2350.00	2350.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2261.65	2261.65
Wheat New Indore (N)	1 Q	2330.00	2330.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2185.00	2150.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2314.40	2335.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	6000.00	6000.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.15	185.65

* as on Jan 14, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (बुधवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19890, 19950, 19730, 19790	4277	709	20217
Feb 28	20130, 20240, 20020, 20070	2823	436	9320
Mar 31	20450, 20450, 20380, 20390	55	5	1284
Apr 30	20330, 20330, 20330, 20330	04	1	13
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2098, 2100, 2051, 2069	2430	132	6860
Feb 20	2119, 2126, 2071, 2077	44410	2895	96990
Mar 20	2146, 2152, 2099, 2104	6440	546	13680
Apr 20	2172, 2173, 2124, 2128	1270	119	5220
May 20	2200, 2200, 2162, 2185	300	27	370
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1135, 1135, 1124, 1126	196	45	832
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1133.5, 1137, 1124.5, 1126.5	1102	608	4799
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4138, 4150, 4090, 4096	3075	102	5375
Feb 20	4174, 4190, 4116, 4132	25305	2658	89435
Mar 20	4224, 4228, 4168, 4176	1665	230	3105
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4136, 4158, 4106, 4126	2135	99	5235
Feb 20	4136, 4190, 4124, 4144	5415	537	25745
Mar 20	4158, 4208, 4156, 4170	1085	151	7235
Apr 20	4210, 4210, 4172, 4192	160	32	3015
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	824.4, 827.1, 799.8, 805.3	21000	1558	34850
Feb 28	828, 830, 802, 807.5	24770	1546	29510
Mar 31	823.5, 826, 797, 802.9	1440	124	6940
Apr 30	806.1, 806.1, 806.1, 806.1	30	2	200
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1281, 1283.7, 1272.5, 1274.2	75.24	174	259.2
Feb 28	1290, 1290, 1283, 1284.7	9.72	25	38.88
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4360, 4451, 4341, 4367	410	39	2900
Feb 20	4406, 4419, 4331, 4346	13220	1064	13930
Apr 20	4425, 4440, 4375, 4386	7800	665	10630
May 20	4412, 4412, 4391, 4395	260	23	1250
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	932, 935.8, 917.6, 919.8	4460	365	7005
Feb 20	914, 915.6, 898.2, 903.4	30860	3197	64010
Mar 20	907.6, 908, 890, 894.2	4130	599	25355
Apr 20	900.2, 902.6, 885, 889.6	515	94	2815
May 20	898.2, 898.2, 897.6, 897.6	40	8	30
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4252, 4266, 4220, 4236	8035	736	10115
Feb 20	4258, 4270, 4192, 4200	46165	5042	196550
Mar 20	4258, 4274, 4202, 4212	14405	1633	105380
Apr 20	4284, 4284, 4226, 4232	5665	593	31380
May 20	4302, 4308, 4268, 4272	555	93	2425
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7360, 7362, 7248, 7324	290	38	370
Feb 20	7460, 7480, 7330, 7348	8360	1238	58425
Mar 20	7571, 7571, 7437, 7445	2325	243	7960
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4475, 4480, 4460, 4470	1540	92	3150
Mar 20	4355, 4370, 4330, 4344	7170	485	22600
Apr 20	4336, 4345, 4328, 4336	790	53	2990
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3800, 3840, 3800, 3820	0.2	2	7.2
Mar 13	3755, 3755, 3755, 3755	0.1	1	1.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6450, 6470, 6391, 6436	1170	108	3080
Apr 20	6961, 7065, 6950, 6988	1490	134	9460
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15720, 15740, 15595, 15595	18	5	78
Mar 20	15300, 15440, 15115, 15150	1179	340	1893
Apr 20	15100, 15100, 14905, 14960	309	99	741
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6398, 6496, 6346, 6412	1055	199	5640
Apr 20	6300, 6358, 6262, 6318	380	73	4630
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	140.25, 140.4, 139.6, 140.3	3951	2683	4742
Feb 28	140.7, 140.9, 140.25, 140.85	178	154	1376
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	452.95, 453.65, 450.5, 453.3	12892.5	4176	12790
Feb 28	453.6, 454.25, 452.35, 453.9	705	250	3812.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	151.95, 153.15, 151.95, 152.8	6006	3650	5903
Feb 28	152.1, 153, 152.1, 152.85	327	269	1123
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	1018.4, 1026.9, 1009.5, 1019.1	13309.5	7699	3255
Feb 28	1009.8, 1018.4, 1002.3, 1011.8	333	209	622.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	183.65, 185.75, 183.65, 184.35	7	7	5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	182.3, 182.4, 181.6, 182.25	10500	6073	17997
Feb 28	182.65, 182.85, 182.3, 182.8	224	192	5111
Mar 31	183.45, 183.45, 183.45, 183.45	1	1	8
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	39646, 39708, 39607, 39634	4.71	4016	12.14
Apr 03	39799, 39827, 39740, 39768	0.45	333	10.9

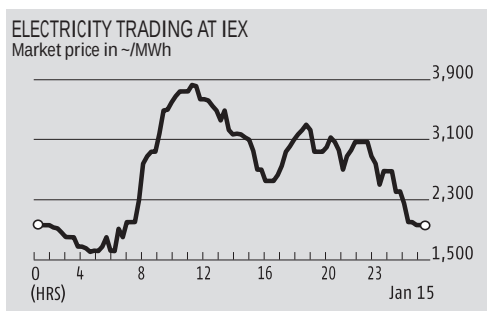

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jun 05	39905, 39917, 39858, 39901	0.07	58	0.33
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	31601, 31814, 31601, 31733	0	240	0
Fe

बेजोस के आकर्षण से मुग्ध दर्शक

एमेजॉन इंडिया के 'संभव' कार्यक्रम में लिया हिस्सा, ट्वीट कर भारत आगमन की घोषणा की थी

शुभायन चक्रवर्ती और नेहा अलावधी

दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर के ठंड में कुछ हफ्ते तक दंगा नियंत्रण ड्यूटी करने के बाद दिल्ली पुलिस के एक सिपाही शैलेंद्र सिंह बुधवार की सुबह काफी राहत वाली मुद्रा में थे। यहां किसी कंसर्ट या खेल के इवेंट के आयोजन का मौका नहीं था। शैलेंद्र सिंह ने स्टेडियम के बाहर दिख रही लंबी कतार के बारे में कहा, 'यहां आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी आया है।'

लघु एवं मझोले उपक्रमों पर आयोजित अमेजन 'संभव' सम्मेलन के लिए यहां तड़के पहुंचने वाले दर्शकों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे एमेजॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ बेजोस से रूबरू हो पाएंगे। इस कार्यक्रम में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी के ज्यादातर साझेदारों को हिस्सा लेना था। एमेजॉन इंडिया इसकी मेजबानी कर रही थी लेकिन इसमें बेजोस के शिरकत करने की जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि बेजोस ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मंगलवार को ही ट्विटर पर अपने आगमन की घोषणा कर दी। भारत आगमन के तुरंत बाद ही ट्वीट की गई एक तस्वीर में बेजोस राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे थे। यह तस्वीर पल भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

फोटोः दलीप कुमार

बेजोस से प्रभावित एक कारोबारी प्रतीक शर्मा ने बताया, 'वास्तव में नेतृत्व करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वह ताकतवर होने के बावजूद कितने विनम्र हैं।' केवल शर्मा ही नहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोगों की ऐसी ही प्रतिक्रिया थी जिन्होंने इसमें हिस्सा लेने के लिए मोटी रकम खर्च की थी।

बेजोस ने भीड़ को निराश नहीं किया। बेजोस ने उत्साह से भरी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की समृद्धि में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। मैंने जो जैकेट पहना है उसे एक छोटे एवं मझोले कारोबारियों ने ही दिया है।' बेजोस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यह जैकेट पहनी थी जो नेहरू जैकेट या मोदी जैकेट के नाम से मशहूर है।

कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह उत्साहित था, लेकिन प्रमुख वक्ताओं में से एक इन्फोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति साफ तौर पर कार्यक्रम के देरी से शुरू होने से खफा थे। उन्होंने कहा, 'कार्यक्रम डेढ़ घंटा देरी से शुरू हुआ है। मुझे 20 मिनट बोलना था, लेकिन अब मैं अपना संबोधन पांच मिनट में ही खत्म करूंगा क्योंकि

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते जेफ बेजोस

मुझे देर करने की आदत नहीं है।' उन्होंने मंच से बिना लाग-लपेट के अपनी बात रखी। अपने शब्दों पर कायम रहते हुए उन्होंने ठीक पांच मिनट बाद अपना माइक्रोफोन बंद कर दिया।

दर्शकों ने एमेजॉन के कार्यक्रम की तुलना गूगल इंडिया के कार्यक्रम से की। गूगल इंडिया ने पिछले सितंबर में इसी जगह पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि गूगल का कार्यक्रम अच्छे कतार प्रबंधन, स्पष्ट साइन बोर्ड और सभी के लिए वाईफाई की वजह से बेहतर था। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि आयोजकों ने समय का पूरा ध्यान रखा। व्यापारियों की संस्था कैट के विरोध के बावजूद एमेजॉन के कार्यक्रम 'संभव' में गजब का उत्साह देखने को मिला। कैट ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जा रही भारी छूट के विरोध में देश भर में 300 स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन किया।

कारोबारियों के विरोध से बेखबर बेजोस करीब 25 मिनट एमेजॉन के भारत में प्रमुख अमित अग्रवाल से बातचीत करते दिखे। बेजोस के संबोधन के बाद जयपुर में एक छोटे फैशन बुटिक के मालिक राजेश ने कहा, 'इस कार्यक्रम की वजह से मुझे दिल्ली आने का मौका मिला है। छोटे विक्रेताओं को पंजीकृत होने के लिए कहना सही नहीं है क्योंकि हम जैसे मौजूदा विक्रेताओं को ही पर्याप्त कारोबार नहीं मिल रहा है।'

कुछ अन्य विक्रेताओं ने कहा कि इस बड़े मंच पर उनके उत्पाद दिख नहीं पाते हैं। उन्होंने इस बारे में एमेजॉन से बातचीत करने के लिए इंतजार किया। हालांकि एमेजॉन के लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि इस मंच पर जरूरत से अधिक विक्रेता मौजूद हैं। इसके बजाय वे वही बात दोहराते हैं जो बेजोस ने अपने संबोधन में कही थी कि 21वीं सदी भारत की है।

जम्मू कश्मीर में मंत्रियों का दौरा

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के सकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए केंद्र के मंत्रियों का समूह इस महीने के अंत में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का समूह सरकार द्वारा उठाए गए विकास के कदमों को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साझा करेगा। मंत्रियों के जम्मू कश्मीर यात्रा कार्यक्रम को 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि यह यात्रा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक पहल है और मंत्रालय इसमें समन्वय कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के 19 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा किए जाने की उम्मीद है। इस बीच जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के एक शीर्ष आतंकवादी को मार गिराया जबकि उसका एक साथी भाग निकलने में सफल रहा। वहीं पुलवामा जिले के अवंतिपुरा इलाके से आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया।

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी सी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र में हालात सामान्य हैं और लोग विकास प्रक्रियाओं में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में तेज विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

सेना प्रमुख एम एम नरवणे

ऐतिहासिक कदम

थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान हटाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक कदम करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस कदम का पश्चिमी पड़ोसी (देश) और उसकी ओर से काम करने वालों की योजनाओं पर असर पड़ा है। उनका इशारा निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। जनरल नरवणे ने 72वें थल सेना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं और हम उनका इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएंगे।'

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को केंद्र ने पिछले साल 5 अगस्त को रद्द कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। थल सेना प्रमुख ने कहा, 'जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करना एक ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जम्मू कश्मीर के एकीकरण में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने हमारे पश्चिम पड़ोसी (देश) और उसके ओर से काम करने वालों की योजनाओं को बाधित कर दिया है।

उन्होंने कहा, 'इसने न सिर्फ छद्म युद्ध को रोका है, बल्कि अन्य स्थितियों का भी मुकाबला किया है। चाहे यह एलओसी (नियंत्रण रेखा) हो या एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) हो, हमने सक्रियता और मजबूती से सुरक्षा सुनिश्चित की है।' थल सेना प्रमुख ने कहा कि एलओसी पर हालात जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़े हैं। पिछले हफ्ते के सियाचिन के अपने दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह यह देख कर वह बहुत खुश हैं कि चौकी पर सभी रैंक के कर्मी के मन में विश्वास भरा हुआ है।

बर्खास्तगी की सिफारिश

जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने बुधवार को कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किए गए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दविंदर सिंह को बर्खास्त करने और यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा सिंह को दिए गए वीरता पदक को वापस लेने की भी सिफारिश की है। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी क्योंकि हम ऐसे लोगों को आश्रय या सुरक्षा देने में विश्वास नहीं करते हैं जिनकी बल, राष्ट्र और अपने लोगों के प्रति कोई निष्ठा नहीं है।

एजेंसियां

निवेश से लुभाने की एमेजॉन की कोशिश

पृष्ठ 1 का शेष

एमेजॉन ने भारत में अपना कारोबार और पहुंच बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों में 5 अरब डॉलर की राशि निवेश की है। पिछले कुछ वर्षों में उसने स्थानीय हस्तशिल्पियों और उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर लगाया है। कंपनी ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया है जो अभी जनजातीय मामले मंत्रालय के पास विचाराधीन है। अभी एमेजॉन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर 5.5 लाख विक्रेता हैं और 60,000 से अधिक भारतीय विनिर्माता और ब्रांड इसके जरिये दुनियाभर के उपभोक्ताओं को मेक इन इंडिया उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। एमेजॉन ने साथ ही पड़ोस की किराना दुकानों की मदद के लिए भी योजनाओं की घोषणा की। स्थानीय व्यापारियों ने कंपनी पर भारी छूट देने और सस्ता सामान बेचने का आरोप लगाया है। एमेजॉन ने 2018 में खासतौर पर भारत के लिए एमेजॉन ईजी प्रोग्राम शुरू किया था जिसका अब विस्तार किया जाएगा। इसके तहत ऐसे ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी में मदद की जाएगी जो इससे वाकिफ नहीं हैं। आसपास का कोई प्रशिक्षित दुकानदार इसमें ग्राहक की मदद करेगा। किराना दुकानें अपने ग्राहकों को सही उत्पाद चुनने और एमेजॉन में ऑर्डर करने में मदद के लिए कियोस्क कर सकेंगी। इससे उन्हें बिक्री पर कमीशन मिलेगा। कंपनी ने 'आई हेव स्पेस' प्रोग्राम का विस्तार करने की भी योजना बनाई है। इसके तहत एमेजॉन इंडिया के साझेदार कई शहरों में स्थानीय दुकानदार के साथ मिलकर उनकी दुकान के दो से चार किमी के दायरे में उपभोक्ताओं को साजोसामान की आपूर्ति करेंगे।

दो ग्राम तक के गहनों को हॉलमार्क से छूट

राजेश भयानी

सरकार ने दो ग्राम से कम वजन के सोने के आभूषणों और वस्तुओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें पूरे देश में 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना दिया गया है। फिलहाल चांदी के गहनों और वस्तुओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से बाहर रखा गया है।

वे सभी सराफ जो सोने के आभूषण बेचना चाहते हैं, उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकरण कराना होगा। अब तक 28,849 से कम सराफों ने बीआईएस के पास पंजीकरण कराया है। इनमें से करीब 3,000 सराफों ने हॉलमार्किंग अनिवार्य बनने की संभावना के कारण पिछले तीन महीनों में पंजीकरण कराया है। हालांकि देश में सराफों की तादाद कई गुना अधिक है। जिन सराफों के पास बिना हॉलमार्क के आभूषण हैं, उन्हें यह स्टॉक अगले एक साल की अवधि में बेचना होगा। आभूषण विक्रेता केवल 14, 18 और 22 कैरट के आभूषणों की ही बिक्री कर सकते हैं। अन्य शुद्धता के सोने के आभूषण हॉलमार्क होने के बावजूद नहीं बेचे जा सकेंगे।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर के अध्यक्ष हर्षद

- 2019 के अंत में देश के 234 जिलों में थे 892 हॉलमार्किंग केंद्र
- बीआईएस के पास 28,849 सराफ पंजीकृत
- कुल सराफ 1.5 से 3 लाख के बीच होने का अनुमान
- बीआईएस देश भर में जागरूकता अभियान शुरू करेगा
- सोशल मीडिया अभियान भी जल्द होगा शुरू
- वित्त वर्ष 2018-19 में 4.49 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग
- 40 फीसदी आभूषण हॉलमार्क हैं, लेकिन इसके बारे में औपचारिक सूचना नहीं

अजमेरा ने कहा, 'देश के मौजूदा हॉलमार्किंग केंद्रों के पास देश भर में बनने वाले गहनों की हॉलमार्किंग करने की पर्याप्त क्षमता है। ये केंद्र अपनी क्षमता के 10 से 15 फीसदी पर चल रहे हैं। देश में 10 से 12 हब 80 फीसदी आभूषणों का उत्पादन कर रहे हैं, जहां ये हॉलमार्किंग केंद्र मौजूद हैं।'

सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में निर्यात होने वाले उन आभूषणों को कुछ छूट दी गई है, जो विदेशी खरीदार की मांग के मुताबिक होते हैं। इसके अलावा दो ग्राम से कम वजन के गहनों को छूट दी गई है। वहीं चिकित्सा, दंत, पशु चिकित्सा, वैज्ञानिक या औद्योगिक उद्देश्य में इस्तेमाल होने वाले सोने की वस्तुओं को हॉलमार्किंग से छूट दी गई है। सिल्ली, प्लेट, शीट, फॉइल, रोड, तार, स्ट्रिप, ट्यूब या सिक्के आदि के किसी आकार वाले सोने के उत्पादों को भी छूट दी गई है। छूट की सूची में अपूर्ण वस्तुओं और निर्यात होने वाले उत्पादों को शामिल किया गया है, जिनके हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं होगी।

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा, '14, 18 और 22 कैरट के लिए हॉलमार्किंग का नियम आभूषणों के विनिर्माण पर नहीं बल्कि केवल आभूषणों की बिक्री पर लागू होना चाहिए। जब ग्राहक अपने पुराने आभूषण या सोना लेकर आएं तो उन्हें इसे अपनी पसंद के कैरट के आभूषणों में बदलवाने की मंजूरी दी जानी चाहिए। ग्राहकों को कम से कम 14 कैरट के नए गहने बनवाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसका गरीब लोगों की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जो सिक्के या सोना या पुराने गहने जमा करके कम कैरट के गहने बनवा सकते थे।'

बीआईएस अधिनियम और अधिसूचना के उल्लंघन के लिए जुर्माना उतना ही होगा, जितना अधिनियम में दिया गया है। हालमार्क गहनों पर 22 कैरट को 916 शुद्धता, 14 कैरट को 750 शुद्धता और 14 कैरट को 585 शुद्धता के रूप में अंकित किया जाएगा। बीआईएस के मुताबिक हॉलमार्क उत्पाद पर दिए जाने वाले अन्य ब्योरों में बीआईएस मार्क, हॉलमार्किंग केंद्र का पहचान चिह्न और सराफा का पहचान चिह्न होगा।

भारत शांति व स्थिरता के पक्ष में, मोदी का ईरान को संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि भारत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के पक्ष में है। नई दिल्ली में रायसीना डॉयलाग में भाग लेने आए ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'विदेश मंत्री ने इस क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम पर अपने नजरिये को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भारत की बहुत रुचि है।'

प्रधानमंत्री ने चाबहार परियोजना में प्रगति के लिए ईरानी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। भारत में जरीफ का स्वागत करते हुए मोदी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर सितंबर 2019 में राष्ट्रपति रूहानी के साथ हुई अपनी सौहार्दपूर्ण बैठक को याद किया। प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस बीच नौसेना प्रमुख ने कहा है कि पीएलए के युद्धपोतों द्वारा कई बार हमारे एक्जक्लुजिव इकनोमिक जोन में घुसने की घटनाएं हुई हैं और हमने उन्हें बताया है कि यह हमारे हितों का अतिक्रमण है।

एस जयशंकर से मुलाकात करते ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ

वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत का तरीका व्यवधान डालने वाला नहीं है और यह किसी चुनौती से दूर रहने की तुलना में फैसला लेने में ज्यादा यकीन रखता है। जयशंकर की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब कई देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की व्यापक भूमिका की अपील कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद से दृढता से निपट रहा है। उन्होंने कहा, 'एक वक्त था जब हम बोलते ज्यादा थे और करते कम थे। यह अब बदल रहा है।' उन्होंने रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे तनाव का जिक्र किया और कहा कि वे दो विशिष्ट देश है और अंततः जो कुछ भी होगा वह इसमें शामिल पक्षों पर निर्भर करेगा।

उन्होंने 'भारत का तरीका:वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करने' सत्र के दौरान यह कहा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) से भारत के बाहर होने के बारे में उन्होंने कहा कि जो देश इसका हिस्सा हैं उन पर इसकी जिम्मेदारी है। जयशंकर ने कहा, 'जहां तक आरसीईपी की बात है हमें इसके नफा-नुकसान पर गौर करना होगा। हम आरसीईपी के आर्थिक एवं व्यापारिक गुण-दोष के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे। हम इस पर विचार करने के प्रति अनिच्छुक नहीं हैं।'

एजेंसियां

अमेरिका जाने वाले छात्रों की कम होती तादाद

विनय उमरजी

पिछले कुछ वर्षों से पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। ताजा ओपन डोर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनैशनल एजुकेशन एक्सचेंज के मुताबिक अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की सालाना वृद्धि घट रही है। यह वृद्धि 2016-17 में 12.3 फीसदी थी, जो घटकर 2017-18 में 5.4 फीसदी और 2018-19 में 2.9 फीसदी पर आ गई। चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है, जहां से पढ़ाई के लिए सबसे अधिक छात्र बाहर जाते हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या 2016-17 में 1,86,267 थी, जो 2018-19 में बढ़कर 2,02,014 पर पहुंच गई।

ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल (जीएमएसी) की रिपोर्ट 'अर्ली वॉर्निंग सिगनल्स : विनर्स ऐंड लूजर्स इन ग्लोबल रेस फॉर टैलेंट' में दिखाया गया है कि अमेरिकी बिज़नेस स्कूलों को अपने ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के अंक भेजने वाले भारतीय छात्रों का प्रतिशत टेस्टिंग वर्ष 2014 में 57 फीसदी था, जो टेस्टिंग वर्ष 2018 घटकर 45 फीसदी पर आ गया। इसी अवधि के दौरान जीमैट टेस्ट में हिस्सा लेने वाले और भारतीय बिज़नेस स्कूलों में अपने अंक भेजने वाले भारतीयों का प्रतिशत 15 फीसदी से बढ़कर 19 फीसदी पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्र अनुकूल नीतियों के अभाव, अमेरिका में कड़े वीजा नियमों और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी जगहों के उदार नियमों की वजह से अमेरिका जाने वाले छात्रों की तादाद में गिरावट आ रही है।

जीएमएसी के मुताबिक पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय छात्रों ने अमेरिकी संस्थानों से दूरी बनाई है। यह वर्ष 2014 में 54 फीसदी से घटकर 2018 में 39 फीसदी पर आ गया। उन्होंने इस अवधि के दौरान पसंदीदा जगह के रूप में कनाडा (4.7 फीसदी से बढ़कर 12.2 फीसदी), फ्रांस (2.4 फीसदी से लेकर 8.1 फीसदी), जर्मनी (2.1 फीसदी से 4.4 फीसदी), ब्रिटेन (6.6 फीसदी से 8.3 फीसदी) और सिंगापुर (3.8 फीसदी से 4.9 फीसदी) जैसे देशों को चुना है।

जीएमएसी के चेयरपर्सन बिल बोल्डिंग के मुताबिक परिषद ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्व के कुछ क्षेत्रों में छात्रों की रुचि में अहम कमी दर्ज की है। बोल्डिंग ने रिपोर्ट में कहा कि नीति-निर्माताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों की इन क्षेत्रों में रुचि क्यों कम हो रही है क्योंकि यह अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस बात का शुरुआती संकेत है कि वे प्रतिभाओं की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। रिपोर्ट ने कहा, 'आप्रवासन नीति में बदलाव का हमारी अर्थव्यवस्थाओं के विकास पर असर पड़ सकता है क्योंकि यह स्नातक के बाद काम की मंजूरी से संबंधित है। यहां तक कि बयानबाजी का ही प्रमुख असर पड़ता है। इस तरह हम कुछ ऐसे ठोस सुझाव दे रहे हैं, जिन्हें सरकार प्रतिभाओं की आवक और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने में अपना सकती है।'